ज्वाला एक्सप्रेस न्यूज

सच्ची खबर सबसे पहले

online- jwalaexpress.com

आर.एन.आई. नं. :- CHHHIN/2021/82386

वर्ष - 05, अंक -47 | दुर्ग (छ.ग.), दिनांक 23 जुलाई से 29 जुलाई (प्रत्येक गुरूवार) | पृष्ठ - 8, मूल्य - 05 रुपए

समाचार सार

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुनाफे में 48% की भारी गिरावट

नईदिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंक ऑफ बड़ौदा ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के वित्तीय नतीजों की घोषणा कर दी। बैंक ऑफ बड़ौदा ने शुक्रवार को बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उनका एकीकृत शुद्ध लाभ 48 प्रतिशत घटकर 1,783 करोड़ रुपये रहा। बैंक ने बताया कि लाभ में ये बड़ी गिरावट संयुक्त अरब अमीरात के एनएमसी ग्रुप मामले में अदालत के बाहर हुए समझौते के तहत 5,680 करोड़ रुपये के भुगतान के कारण दर्ज की गई।

14 घंटे तक बंद रहेंगी आधार की ऑनलाइन सेवाएं

नईदिल्ली। आधार ने ऑनलाइन सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले नागरिकों के लिए एक जरूरी सूचना जारी की है। आधार ने 24 जुलाई को भेजे एक नोटिफिकेशन में बताया कि 25 जुलाई को आधार की ऑनलाइन सेवाएं अस्थाई तौर पर बंद रहेंगी। अगर आपको भी आज आधार से जुड़ा कोई जरूरी काम निपटाना है, तो आपके पास शाम 7 बजे तक का समय है। आधार द्वारा भेजे गए नोटिफिकेशन के मुताबिक, एजेंसी के पूरे सिस्टम का मेनटेनेंस किया जाना है।

बॉडी कैमरा लगाकर ड्यूटी करेंगे टीटीई

नईदिल्ली। उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन ने बॉडी वॉर्न कैमरा पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत कर दी है। इस नए सिस्टम के तहत, टिकट चेकिंग कर्मचारी ड्यूटी के दौरान बॉडी वॉर्न कैमरा पहनकर टिकट की जांच करेंगे, जिससे टिकट जांच के दौरान होने वाली प्रत्येक गतिविधि रिकॉर्ड होगी। ये पायलट प्रोजेक्ट उत्तर मध्य रेलवे के जनरल मैनेजर नरेश पाल सिंह के खास निर्देशों के बाद 24 जुलाई से शुरू की गई है। पहले चरण में प्रयागराज मंडल की दो प्रमुख प्रीमियम ट्रेनों प्रयागराज एक्सप्रेस और श्रमशक्ति एक्सप्रेस में ड्यूटी करने वाले टिकट चेकिंग कर्मचारियों को बॉडी वॉर्न कैमरे उपलब्ध कराए गए हैं।

आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 3 की मौत

कटघोरा। कोरबा जिले के कटघोरा से लगे सलोरा छुरी गांव में आकाशीय बिजली का कहर देखने को मिला है, जहां खेत में काम कर रहे 3 ग्रामीणों की आकाशीय बिजली की चपेट में आकर मौत हो गई। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है।

देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा

जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इसका राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर पर फोकस करें। इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र दिया है।

धर्मेंद्र प्रधान

नई दिल्ली (ए)। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट के पेपर लीक विवाद और पिछले कई हफ्तों से चल रहे भारी विरोध प्रदर्शनों और चौतरफा दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेज दिया है। मेडिकल छात्रों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर सरकार की चौतरफा आलोचना हो रही थी और इस इस्तीफे को परीक्षा प्रणाली में जवाबदेही तय करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। बता दें कि, पेपर लीक के बाद कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की और अपने फैसले पर अड़ी रही। आज सरकार और सीजेपी के तीसरे दौर की वार्ता से पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा सौंपा है।

धर्मेंद्र प्रधान ने सोशल मीडिया पर साझा किया पत्र- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे का पत्र जारी किया। जिसमें उन्होंने लिखा- मेरे युवा साथियों, मैं पिछले चार दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है।

देश के युवाओं की अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं- उन्होंने कहा, मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं।

नीट पेपर लीक पर क्या बोले धर्मेंद्र प्रधान?- उन्होंने आगे लिखा, तीन मई 2026 को हुई नीट-यूजी की परीक्षा में अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया एवं पुन: परीक्षा की तारीख की घोषणा की। इसके साथ ही अगले वर्ष से इस परीक्षा को सीबीटी मोड में करने का निर्णय लिया गया।

री-नीट पर धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा?पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, इस दौरान हमारी प्रमुख प्राथमिकता यह रही कि 20 लाख से अधिक छात्रों की परीक्षा सुचारू रूप से आयोजित की जाए।

इसके लिए पूरी सरकार का समन्वित दृष्टिकोण के तहत काम किया गया। इसमें भारत सरकार के साथ राज्य सरकार, खासकर जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही। उन्होंने आगे कहा, साथ ही छात्रों, अभिभावक और माता-पिता के सहयोग से 21 जून 2026 को यह परीक्षा पूर्ण हुई।

धर्मेंद्र प्रधान बोले- छात्रों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे- पहले ही दिन से मैंने इसकी जिम्मेदारी ली और इस परिस्थिति से कभी मुंह नहीं मोड़ा। मेरा यह संकल्प था कि हम किसी भी मेधावी छात्र की संभावना परीक्षा माफिया के कारण खराब नहीं होने देंगे, किसी भी छात्र के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उन्होंने आगे लिखा, 16 जुलाई को घोषित नीट-यूजी के परिणाम संतोषजनक रहे, जिसमें गरीब पृष्ठभूमि से आए कई मेधावी छात्रों को भी सफलता मिली।

आखिर धर्मेंद्र प्रधान को क्यों देना पड़ा इस्तीफा?- केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे पिछले कई हफ्तों से बन रहा भारी सार्वजनिक और राजनीतिक दबाव था। नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा की शुचिता से समझौता होने के आरोपों को लेकर देश के लाखों छात्रों और अभिभावकों में भारी आक्रोश था। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच और कानूनी कार्रवाई पहले से ही चल रही है। विरोधियों और छात्र संगठनों का आरोप था कि केंद्र सरकार परीक्षा से जुड़ी अनियमितताओं को दूर करने और छात्रों की चिंताओं का समय पर समाधान करने में पूरी तरह विफल रही है, जिसके बाद उन्हें नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना पड़ा।

यह लोकतंत्र की जीत है: सोनम वांगचुक

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर जाने-माने शिक्षा सुधारक सोनम वांगचुक ने भी प्रतिक्रिया दी है। बता दें कि, सोनम वांगचुक ने जंतर-मंतर पर 20 दिन तक अनशन किया था। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनाम वांगचुक ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा- यह लोकतंत्र की जीत है, सीधा लोकतंत्र... जो सड़कों से निकला है। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। सीजेपी और देश की जेन जी को बधाई; और उन सभी नागरिकों का धन्यवाद जिन्होंने डर और डर के डर को त्यागकर देश के हर कोने से आवाज उठाई। जवाबदेही से अब सुधार की ओर।

सीजेपी का आंदोलन खत्म करने का एलान, कहा- सरकार ने मान ली मांगें

दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा विरोध प्रदर्शन आखिरकार खत्म हो गया है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने शनिवार को अपना आंदोलन तुरंत प्रभाव से वापस लेने का बड़ा एलान किया। यह घोषणा केंद्र सरकार के साथ तीसरे दौर की बातचीत के बाद हुई। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया।

केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने शनिवार को सीजेपी के दो सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में सीजेपी के सौरव दास शामिल थे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत का तीसरा दौर सकारात्मक रहा। वार्ता के तुरंत बाद सीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर धरना समाप्त करने की घोषणा की। पार्टी ने देश भर से आए प्रदर्शनकारियों से शांतिपूर्वक अपने घर लौटने की अपील की है।

सौरव दास ने सरकार से बातचीत की सारी जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि हमारी दूसरी मांग यह थी कि

प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर न केवल दिल्ली में बल्कि सभी भाजपा-शासित और भाजपा-सहयोगी राज्यों में वापस ली जानी चाहिए। यह हमारी दूसरी मांग थी। सरकार ने उस मांग को भी मान लिया है। साथ ही, इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने हमें भरोसा दिलाया है कि वह दर्ज सभी एफआईर की कॉपी शेयर करेगी। हमारी आखिरी जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 15 से 20 एफआईआर दर्ज की गई थीं और हमें किसी भी हाल में तीन से चार दिनों के भीतर वे कॉपी मिल जाएंगी। सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया है कि इन्हें जल्द ही वापस ले लिया जाएगा। इसे समझते हुए, हमने सरकार के साथ एक ड्राफ्ट शेयर किया है, जो एक लिखित गारंटी है। सरकार ने कहा है कि वह मंगलवार तक इसे हमारे साथ शेयर करेगी। हमें उम्मीद है कि मंगलवार तक हमें इन एफआईआर और भविष्य की किसी भी कार्रवाई के संबंध में सरकार की गारंटी मिल जाएगी।

पीएम से मेरी बातचीत का नतीजा: शरद पवार

मुंबई। केंद्र सरकार की ओर से धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे समेत अन्य दो मांगें मान लिए जाने के बाद जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने प्रदर्शन खत्म करने का एलान कर दिया है। इस बीच एनसीपी (एसपी) के नेता शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर चौंकाने वाला दावा किया है। शरद पवार ने दावा किया कि उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ही धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की वजह बनी। शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि उन्होंने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्रों और सरकार के बीच सौहार्दपूर्ण संवाद स्थापित करने का प्रयास किया था। उन्होंने दावा किया कि इसी चर्चा के नतीजे के तौर पर शिक्षा मंत्री ने आज इस्तीफा दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी) नेता शरद पवार ने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कहा कि यह देश की युवा शक्ति की बड़ी जीत है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने प्रदर्शनकारियों की मांग पर इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से खड़े होकर और दमन से न डरते हुए सरकार को नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया।

पीएम मोदी मांगे माफी; छात्रों पर हिंसा के लिए अमित शाह जिम्मेदार: राहुल गांधी

दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) की ओर से आंदोलन समाप्ति के एलान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के तुरंत बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था कभी दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती थी, उस पर पिछले कुछ वर्षों में लगातार हमले किए गए हैं, उस पर कब्जा कर लिया गया है और उसका निजीकरण कर दिया गया है।

राहुल गांधी ने कहा कि यह देश के छात्रों की जीत है और शिक्षा प्रणाली की रक्षा की एक बड़ी प्रतिक्रिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जो शिक्षा प्रणाली कभी भारत की शान हुआ करती थी, उस पर पिछले कुछ वर्षों से लगातार हमले हो रहे हैं, उसका व्यवसायीकरण किया जा रहा है और उस पर वैचारिक कब्ज़ा जमाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने निवर्तमान शिक्षा मंत्री को इस प्रशासनिक नाकामी, भ्रष्टाचार और शिक्षा व्यवस्था के विनाश का प्रतीक बताते हुए कहा कि उनका जाना सही कदम है, लेकिन समस्या केवल एक व्यक्ति के हटने से खत्म नहीं होती। राहुल गांधी ने आगे कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा शैक्षणिक संस्थानों को नियंत्रित करना एक गंभीर मुद्दा है और इसके लिए सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं, बल्कि संघ भी उतना ही जिम्मेदार है। शिक्षा व्यवस्था अंदर से पूरी तरह खोखली हो चुकी है और इसे ठीक करने के लिए कड़े व बुनियादी कदम उठाने की ज़रूरत है।

धर्मेंद्र प्रधान को वापस लेना चाहिए इस्तीफा: शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव

दुर्ग। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि धर्मेंद्र प्रधान को अपना इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए। किसी एक व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को इस्तीफा नहीं देना चाहिए।

शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा है कि एक विभाग में कई हजार कर्मचारी काम करते हैं। ऐसे में किसी अन्य व्यक्ति की गलती के लिए मंत्री को जिम्मेदार ठहराकर इस्तीफा मांगना उचित नहीं है। कोई भी मंत्री नहीं चाहेगा कि उसके विभाग में इस तरह से पेपर लीक हो। गजेंद्र यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के कार्यों की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। पुरानी मैकाले शिक्षा पद्धति में बदलाव करते हुए नई शिक्षा नीति लाने में धर्मेंद्र प्रधान की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार और नई शिक्षा नीति के माध्यम से देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा वापस लिया जाना चाहिए।

रामगोपाल अग्रवाल की रिमांड 5 अगस्त तक बढ़ी

जेल जाने से पहले भूपेश बघेल ने की मुलाकात

रायपुर। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला मामले में आरोपी कांग्रेस नेता रामगोपाल अग्रवाल को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां अदालत ने उनकी न्यायिक हिरासत 5 अगस्त तक बढ़ाई।

इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल समेत कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता रायपुर कोर्ट पहुंचे और जेल भेजे जाने से पहले रामगोपाल अग्रवाल से मुलाकात की। बघेल ने कहा कि राजनीतिक लाभ लेने और पार्टी को बदनाम करने के उद्देश्य से सरकार केंद्रीय व राज्य की जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है।

EOW और ED के अनुसार, रामगोपाल अग्रवाल पर शराब घोटाले, कोल लेवी (कोयला लेवी) और कस्टम मिलिंग से जुटाए गए अवैध पैसों को

ठिकाने लगाने (मनी लॉन्ड्रिंग) में मुख्य भूमिका निभाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि कोयला घोटाले से जुड़े 52 करोड़ रुपये के ट्रांसफर में देवेंद्र डड़सेना की भूमिका रही है। रामगोपाल अग्रवाल और देवेंद्र डड़सेना से करीब तीन घंटे तक संयुक्त पूछताछ की गई थी, लेकिन रामगोपाल किसी भी तरह की राशि के ट्रांसफर से इनकार किए। जांच एजेंसी का दावा है कि रामगोपाल अग्रवाल के माध्यम से कोयला, शराब और कस्टम मिलिंग घोटालों से जुड़े करीब 800 करोड़ रुपये इधर-उधर ट्रांसफर किए गए। हालांकि रामगोपाल अग्रवाल इन सभी आरोपों को खारिज किए थे।

शराब कारोबार में 3,400 करोड़ का हुआ है घोटाला : जांच एजेंसी- कोयला घोटाला मामले में रिमांड अवधि समाप्त होने के बाद ईओडब्ल्यू-एसीबी ने उन्हें शराब घोटाला मामले में भी गिरफ्तार किया है। इस मामले में वे न्यायिक रिमांड पर थे। आज रिमांड खत्म होने पर रामगोपाल को कोर्ट में पेश किया गया, जहां 5 अगस्त तक रिमांड बढ़ा दी गई है। बता दें कि रविवार को जांच एजेंसी रामगोपाल अग्रवाल को सेंट्रल जेल ले गई थी, जहां शराब घोटाला मामले के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर के सामने बैठाकर पूछताछ की थी। जांच एजेंसी का दावा है कि शराब कारोबार में करीब 3,400 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है।

महामाया पहाड़ में युवती का मिला कंकाल, शिनाख्त के प्रयास जारी

अंबिकापुर। अंबिकापुर में महामाया पहाड़ पर शनिवार को युवती का कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया है. शव का कुछ हिस्सा पेड़ पर लटका हुआ था. घटना स्थल से कपड़े, ब्रेसलेट और दवाईयां भी मिली है. हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में मृतिका की पहचान नहीं हो पाई है. मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है. जानकारी के मुताबिक, महामाया पहाड़ पर वनकर्मी ने पुरानी लाश को पेड़ पर लटका हुआ देखा. एक हिस्सा पेड़ से लटका हुआ था, तो धड़ नीचे गिरा हुआ था सूचना के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. शव की हालत देखकर फोरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया गया।

भारतीय डाक और फ्लिपकार्ट के बीच हुई अहम साझेदारी

दूर-दराज के इलाकों में पार्सल पहुंचाएंगे डाकिए

नईदिल्ली (ए)। भारत के ई-कॉमर्स लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए पार्टनरशिप की है। देश में दूर-दराज के इलाकों में डिलीवरी क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में, डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

शुक्रवार को दिल्ली में डाक विभाग और फ्लिपकार्ट इंडिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी का उद्देश्य डाक विभाग

की बेजोड़ पहुंच और भरोसेमंद डिलीवरी नेटवर्क के साथ-साथ भारत के ई-कॉमर्स सेक्टर में फ्लिपकार्ट की मजबूत उपस्थिति का लाभ उठाकर पूरे देश में कुशल, विश्वसनीय और ग्राहक-केंद्रित पार्सल डिलीवरी समाधान प्रदान करना है। समझौते के तहत, डाक विभाग पूरे भारत में फ्लिपकार्ट शिपमेंट के लिए अंतिम दूरी तक डिलीवरी सेवाएं प्रदान करेगा। फ्लिपकार्ट, दूर-दराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी, अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पार्सल डिलीवरी सेवाओं के लिए इंडिया पोस्ट के व्यापक नेटवर्क का इस्तेमाल करेगा। इन सेवाओं में प्रीपेड और कैश ऑन डिलीवरी पार्सल की डिलीवरी, ओटीपी आधारित डिलीवरी प्रमाणीकरण और रियल-टाइम शिपमेंट ट्रैकिंग शामिल हैं। ये समझौता कुशल पार्सल आवागमन और वितरण के लिए तेज डिलीवरी, बेहतर परिचालन समन्वय और निर्बाध प्रौद्योगिकी एकीकरण पर केंद्रित है। इस सहयोग से भारत के तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स क्षेत्र को समर्थन देने वाले लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और भी ज्यादा मजबूती मिलने की उम्मीद है। इस साझेदारी के माध्यम से, फ्लिपकार्ट को डाक विभाग के 1.6 लाख से ज्यादा डाकघरों के विशाल नेटवर्क और पूरे भारत में अद्वितीय वितरण नेटवर्क तक पहुंच प्राप्त होगी। इससे बाजार तक व्यापक पहुंच, वितरण दक्षता में सुधार और विशेष रूप से दूरस्थ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर सेवा प्रदान करने में सहायता मिलेगी। बताते चलें कि इससे पहले अमेजन इंडिया ने दूर-दराज के इलाकों में सामानों की डिलीवरी पहुंचाने के लिए भारतीय डाक के साथ साझेदारी की थी।

प्रियंका गांधी का पीएम पर निशाना

वायनाड (ए)। धर्मेंद्र प्रधान ने शनिवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस दौरान कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्होंने हिम्मत, साहस, जिम्मेदारी और नेतृत्व दिखाना होगा।

उन्होंने कल्डी में भूस्खलन स्थल का पहली बार दौरा किया, जहां इस आपदा में आठ लोगों की जान चली गई थी। उन्होंने लोगों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि उन्होंने हिम्मत, साहस, जिम्मेदारी और नेतृत्व दिखाना होगा। कांग्रेस सांसद सुबह कन्नूर हवाई अड्डे पर उतरे और सड़क मार्ग से वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के मेप्पडी में भूस्खलन स्थल की ओर रवाना

हुए। आपदा स्थल की ओर जाते समय, वाड्रा का स्वागत वायनाड इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने किया।

पार्टी सूत्रों ने बताया कि यह छात्रों नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ दिल्ली में छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। इसके बाद वह दोपहर करीब 2 बजे अनाक्कम्पॉयिल सुरंग सड़क परियोजना के पास आपदा स्थल पर पहुंची और कुछ बचे हुए लोगों से मिली, और उनसे सुना कि वे कैसे बाल-बाल बचे।

सूत्रों के अनुसार, वह घटना में घायल हुए उन लोगों से मिलने जाएंगी जिनका इलाज यहां डब्लूआईएमएस अस्पताल में चल रहा है। इसके साथ ही उस स्थल का भी दौरा करेंगी जहां कांग्रेस चोरालमाला भूस्खलन के पीड़ितों के लिए घर बना रही है। 7 जुलाई को अनाक्कम्पॉयिल-मेप्पडी सुरंग परियोजना के स्थल पर हुए भूस्खलन में आठ लोगों की मौत हो गई, जिसका उद्देश्य वायनाड और कोझिकोड जिलों को जोड़ना है।

सुरक्षित बेटी-सशक्त समाज : अंतागढ़ में पुलिस का महिला सुरक्षा एवं साइबर जागरूकता अभियान, 300 से अधिक छात्राएं हुईं जागरूक

कांकेर। उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस द्वारा क्षेत्र में अपराध नियंत्रण और जन-जागरूकता के लिए लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 'सुरक्षित बेटी-सशक्त समाज' की दिशा में कदम बढ़ाते हुए अंतागढ़ पुलिस और महिला रक्षा टीम द्वारा एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पीएम स्वामी आत्मानंद शासकीय विद्यालय अंतागढ़ में आयोजित इस शिविर में 300 से अधिक छात्राओं को महिला सुरक्षा, आत्मरक्षा के नियमों और बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया।

यह पूरा कार्यक्रम पुलिस अधीक्षक कांकेर निखिल राखेचा के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशीष कुमार बंछोर के मार्गदर्शन तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी अंतागढ़ शुभम तिवारी एवं उप पुलिस अधीक्षक प्रतिभा लहरें के पर्यवेक्षण में आयोजित किया गया। पुलिस की महिला रक्षा टीम ने स्कूल पहुंचकर छात्राओं को उनके कानूनी अधिकारों की जानकारी दी और विपरीत परिस्थितियों में अपनी सुरक्षा खुद कैसे करें, इसके व्यावहारिक तरीके सिखाए।

गुड टच-बैड टच और सुरक्षा उपायों की दी जानकारी

कार्यक्रम के दौरान महिला रक्षा टीम के सदस्यों ने छात्राओं को गुड टच-बैड टच, बाल अपराध और महिला सुरक्षा से जुड़े विभिन्न पहलुओं की विस्तृत जानकारी दी। छात्राओं को छत्तीसगढ़ पुलिस के 'अभिव्यक्ति ऐप' के बारे में बताया गया और इसे मोबाइल में डाउनलोड करने व आपातकाल में उपयोग करने का तरीका समझाया गया। टीम ने छात्राओं को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी देते हुए संवाद्यात्मक तरीके से उनकी शंकाओं का समाधान किया, ताकि वे स्वयं जागरूक होने के साथ-साथ अपने परिवार और समाज को भी जागरूक कर सकें।

बढ़ते साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट से बचने की सलाह वर्तमान समय में तेजी से बढ़ते साइबर और सोशल मीडिया फ्रॉड को देखते हुए साइबर टीम ने छात्राओं को विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दी। शिविर में उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने डिजिटल अरेस्ट, बैंकिंग फ्रॉड, ऑनलाइन ठगी, फर्जी लिंक, ऑनलाइन गेमिंग, साइबर बुलिंग, फेक प्रोफाइल, लॉटरी एवं नौकरी के नाम पर होने वाले फ्रॉड के बारे में विस्तार से समझाया। छात्राओं को हिदायत दी गई कि वे सोशल मीडिया पर किसी भी अनजान व्यक्ति से मित्रता न करें और अपना ओटीपी, बैंक खाता नंबर, एटीएम पिन, यूपीआई पिन व अन्य व्यक्तिगत जानकारियां किसी के साथ भी साझा न करें।यह रहे उपस्थित इस गरिमामयी और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में थाना अंतागढ़ से उप निरीक्षक हेमलता परिहार, पीएसआई लता सिंह, महिला रक्षा टीम के सदस्य, विद्यालय के प्राचार्य, शिक्षकगण सहित 300 से अधिक छात्राएं उपस्थित रहीं। कांकेर पुलिस की आम नागरिकों से अपील उत्तर बस्तर कांकेर पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे महिलाओं एवं बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराध, साइबर ठगी, मानव तस्करी, बाल श्रम अथवा किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें। नागरिक अपनी सूचनाएं निकटतम पुलिस थाना, डायल 112, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 अथवा महिला रक्षा टीम के हेल्पलाइन नंबर 9479155925 पर दे सकते हैं। पुलिस का कहना है कि सजग नागरिकों की एक छोटी सी सूचना किसी की सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवन बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण से बढ़ी मजदूरी, हितग्राही ने जताया आभार

विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण से बढ़ी मजदूरी, हितग्राही ने जताया आभार

उत्तर बस्तर कांकेर । भारत सरकार द्वारा विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण (वीबी-जीरामजी) के अंतर्गत ग्रामीण श्रमिकों की मजदूरी दर निर्धारित की गई है, इससे ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत श्रमिकों को आर्थिक मिलेगा। कांकेर विकासखंड के ग्राम बेवरती निवासी मती धनेश्वरी साहू ने बताया कि पहले उन्हें महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत 261 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी। अब विकसित भारत, रोजगार एवं आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण के तहत उन्हें 300 रुपये प्रतिदिन की मजदूरी मिलेगी। उन्होंने कहा कि मजदूरी दर में हुई वृद्धि से ग्रामीण श्रमिकों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा परिवार की दैनिक जरूरतों को पूरा करने में आसानी होगी। इस पहल के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार का यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों के लिए लाभकारी साबित हो रहा है।

बस स्टॉपेज व्यवस्था को लेकर जिला परिवहन कार्यालय में हुई बैठक

कोंडागांव। कलेक्टर मती नूपुर राशि पन्ना के निर्देशानुसार जिला परिवहन कार्यालय कोण्डागांव में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें समस्त बस संचालक एवं उनके प्रतिनिधियों व ऑटो चालक संघ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक में बसों के संचालको को निर्देशित किया गया कि शहर के भीतर निर्धारित स्टॉपेज पर ही बसों को रोकना सुनिश्चित करने व अनाधिकृत स्थानों पर बसों के ठहराव पर रोक लगाने, यात्रियों की सुविधा एवं सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आवश्यक व्यवस्थाएं करने तथा संबंधित विभागो के मध्य समन्वय स्थापित करने पर विस्तृत चर्चा कर निर्देशित किया गया। बैठक में निर्णय लिया गया कि निर्धारित बस स्टॉपेज मर्दापाल चौक, बंधा गार्डन, गांधी चौक व रायपुर नाका के पास ही बसों को रोका जाए शहर के भीतर अन्य किसी स्थान पर बसों के रोक कर सवारी उतारने / चढाने का कार्य नही किया जायेगा व नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मुख्यरुप से जिला परिवहन अधिकारी रामकुमार ध्रुव, थाना कोतवाली प्रभारी, कोण्डागांव सौरभ उपाध्याय, यातायात प्रभारी मुकेश जोशी वा नगर पालिका कोण्डागांव से अशोक साहू उपस्थित रहे।

बस्तर सांसद महेश कश्यप ने 10 करोड़ से अधिक के सीएसआर कार्यों का किया भूमिपूजन

किरंदुल। कभी नक्सल प्रभावित क्षेत्र के रूप में पहचाना जाने वाला दंतेवाड़ा जिला अब विकास की नई राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा हैं।बस्तर लोकसभा सांसद महेश कश्यप ने शनिवार किरंदुल स्थित एनएमडीसी परियोजना के सीएसआर फंड से 10 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विकास कार्यों का भूमिपूजन किया।यह कार्यक्रम हीरोली ग्राम पंचायत में आयोजित हुआ। हिरोली, गुमियापाल और समलवार ग्राम पंचायतें लंबे समय तक नक्सलियों के भय के कारण चर्चा में रहती थीं।नक्सलवाद के खात्मे के बाद पहली बार किसी सांसद का इस क्षेत्र में पहुंचना स्थानीय लोगों के लिए ऐतिहासिक क्षण साबित हुआ। सांसद महेश कश्यप ने क्षेत्र का जायजा लिया और ग्रामीणों की समस्याओं को

गंभीरता से सुना।

सांसद ने लिया विकास का जायजा-भूमिपूजन समारोह के दौरान सांसद कश्यप ने हिरोली, गुमियापाल और समलवार पंचायतों में सड़क, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र और पेयजल व्यवस्था का निरीक्षण किया। उन्होंने स्कूलों की दयनीय स्थिति (छत से पानी रिसना) और युवाओं को बुनियादी सुविधाओं के अभाव पर चिंता जताई। सांसद ने अधिकारियों को तत्काल निर्देश देते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज की जाए।उन्होंने आश्वासन दिया कि सड़क निर्माण, सोलर लाइटें और अन्य बुनियादी सुविधाओं से क्षेत्र में समग्र विकास होगा।महेश कश्यप ने कहा, ÷इतने वर्षों बाद इस क्षेत्र में विकास कार्य शुरू हो रहे हैं।नक्सलवाद मुक्त बस्तर अब प्रगति का प्रतीक बनेगा। स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल सुविधाएं मिलेंगी।

बस्तर फाइटर्स में 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी, पहले चरण में 1500 युवाओं का होगा चयन

स्थानीय युवाओं को मिलेगा मौका, सरकार ने दिसंबर 2026 तक पहली भर्ती पूरी करने का रखा लक्ष्य

बीजापुर। बस्तर संभाग के युवाओं के लिए राज्य सरकार ने बस्तर फाइटर्स के 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी दी है। पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसे दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। भर्ती में बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।

सरकार का उद्देश्य स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करना है। चयनित अभ्यर्थी कानून व्यवस्था बनाए रखने, नक्सल विरोधी अभियानों में सहयोग करने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। सरकार की योजना भविष्य में स्थानीय युवाओं

की सुरक्षा व्यवस्था में भागीदारी बढ़ाने की है।वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा सहकारिता मंत्री केदार कश्यप ने फैसले का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बस्तर के युवाओं में प्रतिभा और साहस की कमी नहीं है। यह भर्ती उन्हें अपने क्षेत्र की सुरक्षा में योगदान देने के साथ सरकारी सेवा का अवसर भी देगी। कश्यप ने कहा कि सरकार बस्तर में शांति, विकास और युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर लगातार काम कर रही है। उनके मुताबिक बस्तर फाइटर्स की भर्ती से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को स्थानीय स्तर पर मजबूती मिलेगी।

भर्ती की बड़ी बातें

बस्तर फाइटर्स के 5800 पदों पर भर्ती को मंजूरी

पहले चरण में 1500 पदों पर भर्ती, दिसंबर 2026 तक लक्ष्य

भर्ती में बस्तर संभाग के स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता

चयनित अभ्यर्थी नक्सल प्रभावित रहे क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे

कोंडागांव में शुरू हुआ मुनगा पौधरोपण जन आंदोलन

कोंडागांव। कुपोषण से लड़ाई को जनभागीदारी से जोड़ते हुए कोंडागांव जिले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने जिले में सुपोषण की ओर एक कदम बढ़ाते हुए मुनगा पौधरोपण जन आंदोलन की शुरुआत की है। अभियान के तहत सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में मुनगा (सहजन) और विभिन्न फलदार पौधे लगाकर सुपोषण वाटिकाएं विकसित की जाएंगी। इसका उद्देश्य बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को स्थानीय स्तर पर पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है, साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा देना

है।अभियान के शुभारंभ अवसर पर जनप्रतिनिधियों, महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, स्वयं सहायता समूहों, स्कूल प्रबंधन समितियों तथा स्थानीय नागरिकों ने पौधरोपण कर सुपोषण और हरित पर्यावरण के लिए सामूहिक संकल्प लिया। मुनगा पोषण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी पौधा है। इसकी पत्तियों, फलियों, फूलों और बीजों में प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, विटामिन-ए तथा विटामिन-सी सहित अनेक आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं।

हरित दंतेवाड़ा की दिशा में बड़ा कदम : एक दिन में बने 1 लाख से अधिक सीड बॉल

सीड बॉल के जरिए पहाड़ियों और बंजर भूमि में बढ़ेगी हरियाली, ग्रामीणों और महिलाओं की भागीदारी से बना जन-अभियान

दंतेवाड़ा। सीड बॉल निर्माण महाअभियान पर्यावरण संरक्षण और वनीकरण को बढ़ावा देने के लिए एक जन-सहभागी पहल है। इसमें स्थानीय बीजों को मिट्टी और जैविक खाद के मिश्रण में लपेटकर छोटी-छोटी गेंदें (सीड बाल) बनाई जाती हैं, जिन्हें बारिश में खाली या बंजर जमीन पर बिखेर दिया जाता है। दंतेवाड़ा जिले को हरा-भरा बनाने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन और कृषि विभाग ने मिलकर एक दिवसीय सीड बॉल निर्माण महाअभियान आयोजित किया। अभियान में ग्रामीणों, महिला स्व-सहायता समूहों, युवाओं, विद्यार्थियों, किसानों और सामाजिक संगठनों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान एक ही दिन में 1 लाख से अधिक सीड बॉल तैयार किए गए। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व और वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव के मार्गदर्शन में अभियान की कार्ययोजना तैयार की गई। कृषि विभाग ने सीड बॉल निर्माण के लिए स्थानीय जलवायु के अनुकूल मिट्टी, जैविक खाद और महुआ, इमली, हर्रा, बहेड़ा, जामुन, करंज, नीम, चार और खमार जैसी स्थानीय प्रजातियों के बीजों का चयन किया। ग्रामीणों और महिला स्व-सहायता समूहों को सीड बॉल तैयार करने का प्रशिक्षण भी दिया गया। सीड बॉल मिट्टी, जैविक खाद और बीजों से तैयार किए जाते हैं। इन्हें बारिश के मौसम में पहाड़ी, दुर्गम और बंजर क्षेत्रों में फैलाया जाता है। बारिश के पानी से बीजों को नमी मिलती है और वे प्राकृतिक रूप से अंकुरित होकर पौधों का रूप लेते हैं। इस तकनीक में गड्ढे खोदने, नियमित सिंचाई और ट्री-गार्ड की आवश्यकता नहीं होती। इससे कम लागत में बड़े क्षेत्र में हरियाली विकसित की जा सकती है। जिला प्रशासन द्वारा तैयार किए गए सीड बॉल को वन विभाग और स्थानीय समितियों के सहयोग से वन क्षेत्रों, पहाड़ियों और अनुपजाऊ भूमि में फैलाया जाएगा, इससे जिले में हरित आवरण बढ़ाने के साथ-साथ मिट्टी संरक्षण, भूजल संवर्धन और जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलेगा। भविष्य में इन पेड़ों से मिलने वाले लघु वनोपज से ग्रामीणों की आजीविका को भी मजबूती मिलेगी। अभियान में महिला स्व-सहायता समूहों की विशेष भूमिका रही। विद्यार्थियों, किसानों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और स्वयंसेवी संगठनों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एक ही दिन में 1 लाख से अधिक सीड बॉल तैयार कर दंतेवाड़ा ने यह संदेश दिया है कि प्रशासनिक संकल्प, वैज्ञानिक तकनीक और जनभागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण के बड़े लक्ष्य भी हासिल किए जा सकते हैं। यह पहल आने वाले वर्षों में दंतेवाड़ा की पहाड़ियों और वन क्षेत्रों को और अधिक हरा-भरा बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

महादेव घाटी स्थित बटालियन मुख्यालय सहित विभिन्न कंपनियों में हुए कार्यक्रम, जवानों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां

शहीदों को नमन के साथ 196वीं बटालियन ने मनाया 20वां स्थापना दिवस

बीजापुर। महादेव घाटी स्थित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की 196वीं बटालियन का 20वां स्थापना दिवस शनिवार को उत्साह और गरिमा के साथ मनाया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमांडेंट कुमार मनीष ने की। इस अवसर पर द्वितीय कमान अधिकारी दिनेश एवं गोपाल सिंह बुनकर, उप कमांडेंट कुणाल किशोर, सहायक कमांडेंट लोकेश यादव एवं अभिषेक कुमार, चिकित्साधिकारी डॉ. शुभम नितिन पवार सहित बटालियन के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत देश की रक्षा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित कर की गई। कमांडेंट कुमार मनीष ने शहीद स्मारक पर पुष्पचक्र अर्पित कर अमर जवानों को नमन किया। इसके बाद क्वार्टर गार्ड में सलामी दी गई और सैनिक सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में कमांडेंट ने जवानों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा और राष्ट्रसेवा की भावना के साथ कार्य करते रहने का संदेश दिया। बटालियन मुख्यालय के साथ ही विभिन्न

कंपनी मुख्यालयों में भी स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। उसूर में निरीक्षक प्रदीप कुमार मेहता, नाम्बी में सहायक कमांडेंट हरीश कुमार, पुजारीकांकेर में सहायक कमांडेंट अनिल कुमार, ताड़पाला घाटी में सहायक कमांडेंट तरुण कुमार मीणा, ताड़पाला में सहायक कमांडेंट विनोद कुमार, वीरभूमि (पश्चिम बंगाल) में निरीक्षक रोशन लाल गुर्जर तथा कठुआ (जम्मू-कश्मीर) में निरीक्षक रजनीकांत रावत के नेतृत्व में कार्यक्रम आयोजित हुए।शाम को बटालियन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें अधिकारियों और जवानों ने देशभक्ति गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से समां बांधा। कार्यक्रम के समापन पर सभी अधिकारियों और जवानों के लिए सामूहिक भोज का आयोजन किया गया। इस दौरान राष्ट्र की सुरक्षा और जनसेवा के प्रति समर्पण दोहराते हुए भविष्य में भी पूरी निष्ठा से दायित्व निभाने का संकल्प लिया गया।

स्थापना दिवस की खास बातें

शहीद स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित कर वीर जवानों को श्रद्धांजलि

क्वार्टर गार्ड में सलामी और सैनिक सम्मेलन का आयोजन

बटालियन मुख्यालय सहित विभिन्न कंपनी मुख्यालयों में हुए कार्यक्रम

सांस्कृतिक प्रस्तुतियों में जवानों ने दिखाई प्रतिभा

सामूहिक भोज के साथ राष्ट्रसेवा और कर्तव्यनिष्ठा का संकल्प दोहराया

गोंडी संस्कृति, शिक्षा, वैद्यकीय ज्ञान, भाषा, आर्थिक उद्यमिता, व्यापार पर महासभा का राष्ट्रीय कार्यशाला संपन्न

धमतरी। अखिल भारतीय गोंडवाना गोंड महासभा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, सेक्टर 24 नया रायपुर छत्तीसगढ़ में संपन्न हुआ। कार्यशाला में मध्यप्रदेश, तेलंगाना, आंध्रप्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों के सामाजिक प्रमुखों के साथ पूरे देश भर के सामाजिक बुद्धिजीवी, विषय विशेषज्ञ ने समाज के रीति-नीति, संस्कृति, शिक्षा, वैद्यकीय ज्ञान, भाषा, आर्थिक उद्यमिता एवं व्यापार जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अपने विचार रखे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रामविचार नेताम मंत्री आदिम जाति विकास, कृषि विकास एवं किसान कल्याण तथा जैव प्रौद्योगिकी, मछली पालन, पशुधन विकास छत्तीसगढ़ शासन थे। अध्यक्षता शिशुपाल शोरी राष्ट्रीय अध्यक्ष सेनि आईएएस, पूर्व विधायक कांकेर के किया। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में फग्गन सिंह कुलस्ते सांसद मंडला, अध्यक्ष पार्लियामेंट्री कमेटी अनुसूचित जाति जनजाति विभाग भारत सरकार, रवि नारायण नाइक प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय गोंडवाना गोंडवाना गोंड महासभा ओडिसा, कैबिनेट मंत्री ग्रामीण विकास पंचायती राज और पेयजल ओडिसा सरकार, देवेंद्र प्रताप सिंह राज्यसभा सांसद छत्तीसगढ़ थे। विशिष्ट अतिथिगण लता उसेन्डी विधायक, कमल मर्सकोले विधायक बरघाट मध्यप्रदेश, नीलकंठ टेकाम विधायक, भूलन सिंह मरावी विधायक, प्रणव मरपच्ची विधायक गौरेला पेंड्रा मरवाही, रूपसिंह मंडावी अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़, विकास मरकाम अध्यक्ष स्थानीय पादप बोर्ड छत्तीसगढ़, भगत सिंह नेताम, पूर्व विधायक एवं सदस्य, मप्र अजजा आयोग, तिरु.सोयम बापू राव पूर्व सांसद प्रदेश अध्यक्ष गोंड समाज तेलंगाना, तिरु-लक्की राजाराव पूर्व विधायक आंध्रप्रदेश, तिरु.चंदा लिंगैया डोरा पूर्व विधायक पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष, राष्ट्रीय संयोजक राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति तेलंगाना, कमलभान सिंह पूर्व सांसद, अनूप नाग पूर्व विधायक अन्तागढ़, रमेश चंद्र साय पूर्व विधायक उड़ीसा, गुरुचरण नायक पूर्व विधायक मनोहरपुर झारखंड, लक्ष्मी ध्रुव पूर्व विधायक सिहावा, राजाराम तोडेम पूर्व विधायक पूर्व उप नेता प्रतिपक्ष मध्यप्रदेश, पहलवान सिंह मरावी पूर्व विधायक मरवाही उपस्थित थे। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के उभरते हुए कलाकार निर्माता, निर्देशक, हीरो अमलेश नागेश का उनके उत्कृष्ट कार्यो के लिए सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन महासभा के राष्ट्रीय सचिव आर एन ध्रुव ने किया। महासभा द्वारा उड़ीसा के शैक्षिक पाठ्यक्रम में गोंड समाज को मूर्ख लिखे जाने पर निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। साथ ही दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हेतु महामहिम राष्ट्रपति को पत्र लिखा जाएगा। आदिवासी समाज के उद्यमियों को 10 करोड़ तक के ऋण लेने पर गारंटी हेतु छूट प्रदान करने के लिए सरकार से मांग करेगी, जिससे आदिवासी उद्यमी व्यापार व्यवसाय के क्षेत्र में आगे बढ़ सके। अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान विद्यार्थियों को विदेश में अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति प्रदान करने की मांग सरकार से की जावेगी। गैर आदिवासियों में विवाह करने वाले समाज की युवतियों द्वारा अर्जित किए जाने वाले संपत्ति पर पिता का नाम अंकित करवाने हेतु महासभा ठोस पहल करेगी। महासभा प्रत्येक माह देश के किसी ने किसी प्रदेश में बैठक आहूत करेगी। सभी राज्यों में गौर समाज को अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किए जाने हेतु सरकार से मांग करेगी। आदिवासी क्षेत्र में लग रहे उद्योगों में विस्थापन की स्थिति में आदिवासी वर्ग को उद्योगों में भागीदारीध् शेयर होल्डर बनाए जाने की मांग की जावेगी। पांच सत्र में कार्यक्रम को विभाजित किया गया था। प्रथम सत्र में जनजातीय कला और शिल्प, आर्थिक उद्यमिता एवं व्यापार विषयों पर चर्चा हुई। प्रमुख वक्ता के रूप में प्रोफेसर श्रीकांत गोंड पश्चिम बंगाल, डॉ नारवेन केशव टेकाम छत्तीसगढ़, प्रो के एम मैत्री कर्नाटक ने भाग लिया। द्वितीय में गोंडवाना का इतिहास, भाषा, शिक्षा, संस्कृति, पारंपरिक रीति-रिवाज, साहित्य सृजन पर विस्तृत चर्चा हुई इस सत्र में तिरु.हिरासन उइके राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रभाग बालाघाट मध्यप्रदेश, सांस्कृतिक सचिव रघुवीर सिंह मार्को प्रमुख वक्ता के रूप में तिरु.बी एल कोर्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल गोंडी साहित्य परिषद भारत, तिरु.के पी शाह पूर्व न्यायाधीश कोलकाता पश्चिम बंगाल, तिरु.बजरंग मांझी उड़ीसा ने हिस्सा लिया। तृतीय सत्र पेसा कानून, फॉरेस्ट राइट एक्ट, जनजाति समाज के संवैधानिक अधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन पर चर्चा हुई इस सत्र में तिरु-रूपसिंह मंडावी अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति आयोग छत्तीसगढ़ द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव महासभा को दिए। विकास मरकाम स्थानीय पादप बोर्ड द्वारा परंपरागत आयुर्वेद ज्ञान पर आधारित महत्वपूर्ण जानकारियां दिए। दोपहर भोजन अवकाश के दौरान महासभा गठन से लेकर अब तक के गतिविधियों का डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाया गया। चौथे सत्र में सरकार की जनमन योजना एवं धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना पर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष विधायक केशकाल तिरु-नीलकंठ टेकाम ने समाज को विस्तृत जानकारी दी। पंचम सत्र में गोंडवाना गोंड महासभा के संगठनात्मक ढांचे को मजबूती प्रदान करने एवं संगठन के विस्तार पर चर्चा, संगठन के निष्क्रिय सदस्यों के स्थान पर नए सदस्यों का मनोनयन किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ। अतिथियों एवं सामाजिक प्रमुखों को स्मृति चिन्ह भेंट, सामाजिक प्रमुखों का सम्मान करने के पश्चात सत्र का समापन हुआ। इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष खामसिंह मांझी ओड़िसा, राष्ट्रीय महासचिव लोकेंद्र सिंह कोमर्रा, सोनऊ राम नेताम छग, दिवाकर पेंदाम महाराष्ट्र, हेमंत धुर्वा उड़ीसा, कोषाध्यक्ष हिम्मत सिंह आर्मो, अशोक गोंड बिहार, तेलंगाना, राष्ट्रीय महासचिव महिला प्रभाग कांति नाग छत्तीसगढ़, वेदवती मंडावी, कमला नेताम, स्वर्ण वरकडे महाराष्ट्र, अमरेंद्र प्रताप गोंड उत्तरप्रदेश, चंदन मर्सकोले मध्यप्रदेश, प्रदेश गोंडवाना गोंड महासभा संरक्षक बी पी एस नेताम सेनि आईएएस, प्रदेश उपाध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद ठाकुर, अंबिका प्रसाद शांडिल्य, बलदाऊ सिंह ध्रुव प्रदेश उपाध्यक्ष, प्रांतीय कोषाध्यक्ष फूलसिंह नेताम, भुनेश्वर सिदार, प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रभाग बसंता ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष युवा प्रभाग चेमसिंह मरकाम, प्रदेश महासचिव युवा प्रभाग मिथिलेश कुंजाम, मीडिया प्रभारी रोहित कुमार मरकाम, एम आर ठाकुर, कुंदन सिंह ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित थे।

हृदय जांच शिविर में 18 बच्चे ऑपरेशन के लिए चिन्हित

कवर्धा। जिला चिकित्सालय संबद्ध शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सालय, कबीरधाम में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के अंतर्गत विशेष निःशुल्क ईको कार्डियोग्राफी जांच शिविर का आयोजन किया गया। रायपुर के सुपरस्पेशलिटी अस्पताल के सहयोग से आयोजित इस शिविर में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे 53 बच्चों की हृदय संबंधी जांच की गई। जांच के दौरान 18 बच्चों में गंभीर हृदय संबंधी समस्याएं पाई गई, जिन्हें आगे विशेष उपचार एवं ऑपरेशन के लिए चिन्हित किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार चिन्हित बच्चों का उपचार राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (चिरायु) के तहत शासन की निर्धारित व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह निःशुल्क कराया जाएगा।

आवश्यकता पड़ने पर इन बच्चों को राज्य के अनुबंधित शासकीय एवं निजी अस्पतालों में भर्ती कर उपचार एवं ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। गंभीर मामलों में राज्य के बाहर भी बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं। शिविर का निरीक्षण कलेक्टर गोपाल वर्मा ने किया। उन्होंने शिविर की व्यवस्थाओं, जांच प्रक्रिया तथा चिन्हित बच्चों के उपचार संबंधी तैयारियों की जानकारी स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से प्राप्त की। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कहा कि बच्चों में गंभीर बीमारियों की समय पर पहचान और उपचार अत्यंत आवश्यक है तथा इस दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए जा रहे प्रयास सराहनीय हैं। उन्होंने ऐसे विशेष जांच शिविरों को नियमित रूप से आयोजित करने और पात्र बच्चों को बिना विलंब उपचार उपलब्ध कराने पर जोर दिया। शिविर में रायपुर से पहुंचे पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. चन्द्रकांत उसेंडी ने अपनी विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान कीं। उन्होंने बच्चों की ईको कार्डियोग्राफी जांच कर अभिभावकों को बीमारी की स्थिति एवं आगे की उपचार प्रक्रिया की जानकारी दी। विशेषज्ञ चिकित्सकों ने बताया कि जन्मजात हृदय रोगों की समय पर पहचान होने से बच्चों का सफल उपचार संभव हो पाता है और कई गंभीर स्थितियों से बचाव किया जा सकता है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी साहू, नगर पालिका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश चन्द्रवंशी, जिला पंचायत उपाध्यक्ष कैलाश चन्द्रवंशी, जिला पंचायत सदस्य रामकुमार भट्ट, नितेश अग्रवाल, मनीराम साहू, रिंकेश वैष्णव, मोहन ठाकुर, जितेंद्र सिंह तथा दुर्गेश दुबे सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. देवेंद्र तूरे, शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सलिल मिश्रा, जिला कार्यक्रम प्रबंधक अनुपमा तिवारी, डॉ. मुकुंद राव, आराधना बंजारे, प्रिया तंबोली, चंदन टेकाम तथा चिरायु दल के सदस्यों ने शिविर के सफल संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले के शासकीय एवं अनुदान प्राप्त विद्यालयों, आश्रम-छात्रावासों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अध्ययनरत बच्चों का नियमित स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। चिरायु दल वर्ष में निर्धारित समय पर संस्थानों का भ्रमण कर बच्चों की जांच, परामर्श एवं उपचार की सुविधा उपलब्ध कराता है। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. सलिल मिश्रा ने अभिभावकों से अपील करते हुए कहा कि बच्चों में दूध पीते समय अत्यधिक थकान, अधिक पसीना आना, होंठ या नाखूनों का नीला पड़ना, वजन नहीं बढ़ना, तेज सांस चलना, थोड़े परिश्रम में सांस फूलना, सीने में दर्द, चक्कर आना अथवा बेहोशी जैसे लक्षण दिखाई दें तो इसे सामान्य न समझें। ऐसे संकेत हृदय रोग की ओर इशारा कर सकते हैं। समय पर चिकित्सकीय जांच और उचित उपचार से बच्चों को गंभीर हृदय संबंधी बीमारियों से सुरक्षित रखा जा सकता है।

ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं से अपशिष्ट जल का सुरक्षित निस्तारण

दल्लीराजहरा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत बालोद जिले के विभिन्न ग्रामों में घरेलू उपयोग के बाद निकलने वाले ग्रे-वॉटर (रसोई, स्नानघर एवं कपड़े धोने का पानी) के वैज्ञानिक प्रबंधन हेतु प्रभावी पहल की जा रही है। इसके तहत पेयजल स्त्रोतों के समीप सोकपिट, मैजिक पिट एवं अन्य ग्रे-वॉटर प्रबंधन संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। इन संरचनाओं के माध्यम से अपशिष्ट जल का सुरक्षित निस्तारण सुनिश्चित किया जा रहा है, जिससे गांवों में स्वच्छता को बढ़ावा मिलने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण में भी महत्वपूर्ण योगदान मिल रहा है। पूर्व में घरों से निकलने वाला ग्रे-वॉटर सड़कों एवं गलियों में बहने से जलभराव, गंदगी, दुर्गंध तथा मच्छरों के पनपने जैसी समस्याएं उत्पन्न होती थीं। अब निर्मित सोकपिट एवं मैजिक पिट के माध्यम से यह पानी भूमि में सुरक्षित रूप से समाहित हो रहा है, जिससे जलभराव की समस्या कम हुई है तथा गांव का वातावरण अधिक स्वच्छ एवं स्वस्थ बन रहा है। इन संरचनाओं से भू-जल स्तर के पुनर्भरण को भी बढ़ावा मिल रहा है। वर्षा जल एवं ग्रे-वॉटर के भूमि में समाहित होने से जल स्त्रोतों के संरक्षण में सहायता मिल रही है, जो भविष्य में जल उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ग्रे-वॉटर प्रबंधन से जल प्रदूषण में कमी आने के साथ-साथ खुले में गंदा पानी बहने की समस्या समाप्त हो रही है। इससे संक्रामक बीमारियों के प्रसार का खतरा कम हुआ है तथा ग्रामीणों को स्वच्छ एवं सुरक्षित वातावरण प्राप्त हो रहा है। कई स्थानों पर उपचारित जल का उपयोग पौधारोपण एवं हरित क्षेत्र के संरक्षण में भी किया जा रहा है, जिससे जल का पुनः उपयोग संभव हो रहा है। जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे निर्मित सोकपिट, मैजिक पिट एवं ग्रे-वॉटर संरचनाओं का नियमित उपयोग एवं रखरखाव करें तथा किसी भी प्रकार का ठोस कचरा इनमें न डालें। जनसहभागिता से ही ग्रे-वॉटर प्रबंधन की यह पहल सफल होगी और स्वच्छ, स्वस्थ एवं जल-सुरक्षित गांवों के निर्माण का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकेगा।

जनता की समस्याओं का समाधान मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता : विधायक दीपेश साहू

बेमेतरा। बेमेतरा विधायक दीपेश साहू ने अपने निवास कार्यालय में आयोजित भेंट-मुलाकात कार्यक्रम के दौरान विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों से पहुंचे ग्रामीणों एवं नगरवासियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। बड़ी संख्या में पहुंचे नागरिकों ने स्वच्छ पेयजल, सड़क एवं नाली निर्माण, विद्युत व्यवस्था, सामुदायिक भवन, प्रधानमंत्री आवास, शौचालय निर्माण, स्वास्थ्य सुविधाओं सहित स्थानीय विकास से जुड़ी विभिन्न मांगें विधायक के समक्ष रखीं। विधायक दीपेश साहू ने प्रत्येक नागरिक की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि के रूप में जनता की समस्याओं का समाधान उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है। विधानसभा क्षेत्र का कोई भी नागरिक अपनी समस्या लेकर उनसे सीधे मिल सकता है।

हर वर्ग के विकास के लिए प्रतिबद्ध भाजपा सरकार : विधायक दीपेश साहू

कार्यक्रम के अंत में नागरिकों को संबोधित करते हुए विधायक दीपेश साहू ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में प्रदेश की भाजपा सरकार सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय निर्माण, सड़क-नाली, सामुदायिक भवन, पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य सहित प्रत्येक क्षेत्र में जनहित सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला और युवा सहित समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में विकास की नई धारा बहाने का प्रयास किया जा रहा है। विधायक साहू ने कहा कि जनता की समस्याएं मेरी प्राथमिकता हैं और उनका समाधान हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। आपकी हर उचित मांग पर शीघ्र कार्रवाई होगी और विकास का लाभ विधानसभा क्षेत्र के हर घर तक पहुंचाया जाएगा।

कुर्मी समाज ने विधायक का जताया आभार

इसी दौरान बेमेतरा नगर पालिका में कुर्मी समाज के कमलेश वर्मा को प्रतिनिधित्व मिलने पर समाज के पदाधिकारियों ने विधायक दीपेश साहू से मुलाकात कर उनका आभार व्यक्त किया। कमलेश वर्मा को एल्डरमैन नियुक्त किए जाने पर कुर्मी समाज में खुशी का माहौल है। समाज के पदाधिकारियों ने विधायक कार्यालय पहुंचकर विधायक दीपेश साहू का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर सिंघरौर कुर्मी समाज के जिला अध्यक्ष राजेन्द्र वर्मा, नवनियुक्त एल्डरमैन कमलेश वर्मा, प्रज्वल वर्मा, चम्पेश्वर वर्मा, भाजपा नेता शेखर वर्मा, लच्छन वर्मा, पोषण वर्मा सहित समाज के अन्य पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

प्राथमिक शाला के विद्यार्थियों को कापी पेन व अन्य आवश्यक सामग्री का वितरण

सरायपाली। शासकीय प्राथमिक शाला दर्राभाठा, संकुल केंद्र बैदपाली में विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास एवं अध्ययन के प्रति रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से बच्चों को उपयोगी शैक्षणिक सामग्री का वितरण किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के विद्यार्थियों को पहाड़ा, पेन एवं कॉपी प्रदान की गई। आराध्या स्पोर्ट्स की ओर से पहाड़ा व पंच सुशीला कुमार की और से कॉपी की व्यवस्था की गई थी। विद्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्देश्य बच्चों में नियमित अध्ययन, लेखन अभ्यास एवं गणितीय दक्षता को बढ़ावा देना है। प्राथमिक स्तर पर पहाड़ा सीखना बच्चों की गणितीय समझ को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी उद्देश्य से विद्यार्थियों को पहाड़ा उपलब्ध कराकर उन्हें नियमित अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया गया। वहीं पेन एवं कॉपी के वितरण से बच्चों को लिखने-पढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री उपलब्ध हुई, जिससे उनके अध्ययन कार्य में सुविधा होगी। कार्यक्रम के दौरान बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में बताया गया तथा उन्हें नियमित रूप से विद्यालय आने, प्रतिदिन पढ़ाई करने, लिखने का अभ्यास करने और दिए गए पहाड़ों को याद करने के लिए प्रेरित किया गया। बच्चों ने उत्साहपूर्वक शैक्षणिक सामग्री प्राप्त की और इस पहल के प्रति खुशी व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधान पाठक हृदयराम राम साव ने कहा कि बच्चों को आवश्यक शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराने से उनमें पढ़ाई के प्रति रुचि और उत्साह बढ़ता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए विद्यालय में पढ़ाई के साथ-साथ ऐसी गतिविधियां भी आवश्यक हैं, जो उन्हें सीखने के लिए प्रेरित करें। शिक्षक जयंत बारीक ने कहा कि बच्चों को प्रारंभिक स्तर से ही नियमित अभ्यास की आदत डालना अत्यंत आवश्यक है। पहाड़ा गणितीय दक्षता की नींव मजबूत करता है, जबकि कॉपी और पेन बच्चों में लेखन कौशल विकसित करने में सहायक होते हैं। विद्यालय द्वारा विद्यार्थियों के शैक्षणिक विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। इस अवसर पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता रीबिका कुमार ने अपनी और से सभी बच्चों को कॉपी भेंट किया बच्चों को नियमित रूप से पढ़ाई करने तथा अपने शिक्षकों और अभिभावकों के मार्गदर्शन का पालन करने के लिए प्रेरित किया।

बस स्टैंड पालिका बाजार में व्यापारियों को दुकान आवंटन का इंतजार जल्द होगा समाप्त : विजय

बेमेतरा। नगर पालिका द्वारा बस स्टैंड स्थित पालिका बाजार का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, लेकिन व्यापारियों का अपनी दुकानों में व्यवसाय शुरू करने का सपना अभी तक अधूरा है। वर्तमान में दुकानों के किराया/रेट निर्धारण की फाइल कलेक्टर कार्यालय में स्वीकृति के लिए भेजी गई है। नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने बताया कि रेट निर्धारण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त होते ही नगर पालिका द्वारा पूर्व में अग्रिम आधिपत्य (अस्थायी आवंटन) प्राप्त कर चुके पात्र व्यापारियों को विधिवत दुकानें आवंटित कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि नगर पालिका का उद्देश्य है कि व्यापारियों को शीघ्र उनकी दुकानें उपलब्ध कराई जाएं, जिससे वे अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकें और पालिका बाजार पूरी तरह संचालित होकर नगर के व्यापारिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। नगर पालिका इस प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। जिन लोगों को दुकान आबटन हो चुका है किराया नहीं जमा किया जा रहा है उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी जब से संचालित हो रही है तब से किराया वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

कलेक्टर उइके ने नीट, जेईई जैसे प्रवेश परीक्षा में चयनित विद्यार्थियों को किया सम्मानित

गरियाबंद। कलेक्टर बीएस उइके ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय कोसमबुड़ा के सत्र 2025-26 के विद्यार्थियों ने विभिन्न राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश परीक्षा में चयनित बच्चों को सम्मानित किया। कलेक्टर उइके ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सभाकक्ष में उन्हें मोमेंटो एवं श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। उन्होंने विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं। कलेक्टर ने कहा कि दूरस्थ एवं आदिवासी क्षेत्रों के बच्चों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। उन्हें उचित मार्गदर्शन और अवसर मिलने पर वे राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों की सफलता का श्रेय विद्यालय के प्राचार्य एवं शिक्षकों के समर्पित प्रयासों और मार्गदर्शन को भी दिया। इस दौरान जिला पंचायत के सीईओ प्रखर चंद्राकर, अपर कलेक्टर पंकज डाहिरे, डिप्टी कलेक्टर नेहा भेड़िया, हितेश्वरी बाघे सहित अन्य अधिकारियों ने चयनित अभ्यर्थियों को सम्मानित किया। विद्यालय के प्राचार्य डॉ. कमलाकांत यादव ने जिला प्रशासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि आगामी सत्रों में भी विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों तक पहुंचाने के लिए विद्यालय परिवार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगा। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षकगण भी उपस्थित रहे। विद्यालय के कुल 33 विद्यार्थियों ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त की। इनमें चिकित्सा क्षेत्र के प्रवेश परीक्षा नीट, बीएससी नर्सिंग एवं फार्मेसी में 16 विद्यार्थियों ने, इंजीनियरिंग एवं डिजाइन क्षेत्र के जेईई मेन्स में 4 विद्यार्थियों ने एवं एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम के बीए-बीएड पाठ्यक्रम में 13 विद्यार्थियों का चयन हुआ। इस दौरान सहायक आयुक्त लोकेश पटेल तथा विद्यालय परिवार ने सभी सफल विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया।

गौण खनिज मद से होंगे जनपद में विकास कार्य, 11 कार्यों की स्वीकृति हेतु 8 लाख की अनुशंसा

डोंगरगांव नगर। जनपद पंचायत की सामान्य सभा की बैठक जनपद अध्यक्ष रंजीता पडोती की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में जनपद क्षेत्र में संचालित विकास एवं निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागों के कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। गौण खनिज मद की राशि से विभिन्न विकास कार्यों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई। बैठक में सामान्य प्रशासन, शिक्षा, जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य, वन तथा लोक निर्माण विभाग सहित कुल 24 विभागों की विभागवार समीक्षा की गई। जनपद अध्यक्ष रंजीता पडोती ने सभी विभागीय अधिकारियों को शासन की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने तथा विकास कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता बनाए रखने के निर्देश दिए। सामान्य सभा में गौण खनिज मद से जनपद क्षेत्र की विभिन्न ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं को देखते हुए कुल 11 विकास कार्यों के लिए लगभग 7.95 लाख रुपये की राशि का अनुमोदन कर स्वीकृति हेतु अनुशंसा की गई।

संपादकीय

सोनम वांगचुक का अनशन- संवाद की जगह बल प्रयोग क्यों?

दिल्ली में जंतर-मंतर पर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा जबरन अस्पताल में भर्ती करा देने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।भारत समेत दुनिया भर में अनशन के जरिए व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिशें इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। आजादी के बाद देश के संविधान में अभिव्यक्ति के अधिकार को शामिल किया गया, जिसमें शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन की अनुमति का भी प्रावधान है। संविधान देश के हर नागरिक को यह इजाजत देता है कि वह शासन-प्रशासन, संस्था या किसी समूह की नीतियों और निर्णयों को लेकर कानून के दायरे में रहकर अपना असंतोष प्रकट कर सकता है। ऐसे में सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति को अनशन करने से जबरन रोका जा सकता है?मामला तब और भी संवेदनशील, गंभीर और महत्त्वपूर्ण हो जाता है, जब अनशन देश की व्यवस्था में सुधार के मुद्दे पर केंद्रित हो। दिल्ली में जंतर-मंतर पर पिछले बीस दिन से अनशन कर रहे जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को पुलिस द्वारा शनिवार को जबरन अस्पताल में भर्ती करा देने की घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं।दरअसल, नीट में गड़बड़ियों को लेकर काकरोच जनता पार्टी (काजपा) की ओर से जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारी केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार की मांग कर रहे हैं। सोनम वांगचुक ने इस मांग के समर्थन में अनशन शुरू किया था। उम्मीद की जा रही थी कि सरकार प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर समाधान का कोई रास्ता निकालेगी, लेकिन इसके विपरीत पुलिस ने वांगचुक को जबरन अस्पताल में भर्ती करा दिया। ऐसे में यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या सरकार को असल में वांगचुक के स्वास्थ्य की फिक्र है या फिर यह सब आंदोलन की आवाज को दबाने के प्रयास का हिस्सा है?देश में ऐसी कई घटनाओं के उदाहरण हैं, जब सरकार या उसके प्रतिनिधियों ने आंदोलनकारियों से बातचीत कर उन्हें भरोसे में लेकर अनशन समाप्त कराया है। फिर क्या वजह है कि इस मामले में सरकार को प्रदर्शनकारियों से संवाद की अब तक कोई जरूरत ही महसूस नहीं हुई और अनशन को बलपूर्वक समाप्त कराने की कोशिश को ही प्राथमिकता दी गई।यह सच है कि सोनम वांगचुक के लगातार अनशन से उनकी सेहत बिगड़ रही थी, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने यह कदम उठाया, क्या सरकार के लिए उसका कोई महत्त्व नहीं है? नीट की परीक्षाओं में पर्चालीक और अन्य तरह की गड़बड़ियां अब किसी से छिपी नहीं हैं और सरकार ने भी इसे स्वीकार किया है। ऐसे में अगर युवा वर्ग शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहा है, तो यह सरकार के लिए अप्रासंगिक या महत्त्वहीन विषय कैसे हो सकता है?अनशन के मसले पर दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा था कि जीवन अनमोल है ।

अंदर से दरक रहा पाकिस्तान ! बलूचिस्तान, पीओके और पख्तूनख्वा में मचा असंतोष, भारत के लिए खुले दरवाजे

(ब्रह्मदीप अलूने)

बलूचिस्तान, पीओके और खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ते असंतोष के बीच पाकिस्तान राजनीतिक और आर्थिक संकट से जूझ रहा है। जानें कैसे यह स्थिति भारत के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक अवसर बन सकती है। टूटी हुई आकृति के रूप में दर्शाया गया पाकिस्तान का मानचित्र, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा है–ज्क्या टूट जाएगा पाकिस्तान? यह देश के भीतर बढ़ती राजनीतिक अस्थिरता और अलगाववादी चुनौतियों का सांकेतिक चित्रण है।

पाकिस्तान की राजनीति में सैन्य वर्चस्व ने वहां की लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर किया है, आर्थिक सुधारों को बाधित किया है और कट्टरपंथी संगठनों के प्रति दोहरी नीति को जन्म दिया है। इसके कारण पाकिस्तान आज राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक संकट और आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है। यह स्थिति भारत के लिए अनेक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है।

पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में वहां की हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन की आवाज के बीच भारत का समर्थन देखा जा रहा है। वहीं, बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान को भारत से सीखने की नसीहत दे रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा में पश्तूनी नागरिक पाकिस्तान से ज्यादा भारत के करीब नजर आते हैं।

विरोध के मुखर होते स्वर: पाकिस्तान औपचारिक रूप से पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान प्रांतों को मिलाकर संघीय गणराज्य है। गिलगित-बाल्टिस्तान तथा पीओके अलग प्रशासनिक इकाइयां हैं। पिछले एक दशक में खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, गिलगित-बाल्टिस्तान तथा पीओके में राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मसलों को लेकर असंतोष लगातार बढ़ा है। पीओके तथा गिलगित-बाल्टिस्तान में उभरते राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक असंतोष भारत के लिए कूटनीतिक, रणनीतिक और वैचारिक स्तर पर अपनी स्थिति सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करते हैं। भारत लंबे समय से इन क्षेत्रों को अपने अभिन्न अंग के रूप में मानता है। ऐसे में भारत को यहां की मौजूदा परिस्थितियों को अंतरराष्ट्रीय मंचों पर तथ्यों और मानवाधिकार संबंधी चिंताओं के आधार पर प्रभावी ढंग से उठाने का प्रयास करना चाहिए।

भारत की लोकतांत्रिक साख को पाकिस्तान पर स्वाभाविक बढ़त हासिल है और यही भारत की असल ताकत भी है। लोकतांत्रिक संस्थाएं, स्वतंत्र न्यायपालिका, नियमित चुनाव, स्थानीय स्वशासन और संवैधानिक अधिकार किसी भी क्षेत्र की स्थिरता और विकास के लिए अनिवार्य होते हैं। भारत का लोकतांत्रिक शासन मॉडल और विकास-आधारित दृष्टिकोण दुनिया के सामने है। पाकिस्तान में नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक अधिकारों और प्रशासनिक जवाबदेही जैसे मुद्दों को लेकर लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं।

भारत अंतरराष्ट्रीय कानून और मानवाधिकारों के सार्वभौमिक सिद्धांतों के संदर्भ में इसे पुरजोर तरीके से उठाने के साथ विकास, आधारभूत संरचना, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन और लोकतांत्रिक भागीदारी के क्षेत्र में जम्मू-कश्मीर में हुए परिवर्तनों को वैश्विक समुदाय के समक्ष अधिक प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर दोनों ओर की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना का एक वैकल्पिक विमर्श दुनिया के सामने ला सकता है।

भारत के लिए अवसर: भारत के लिए इस अवसर को कश्मीर को लेकर भ्रम फैलाने की पाकिस्तान की नीति की हकीकत को दुनिया के सामने लाने के एक बड़े मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। गिलगित-बाल्टिस्तान का सामरिक महत्त्व भी है। यह क्षेत्र चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का प्रमुख प्रवेश मार्ग है। यह परियोजना उस क्षेत्र से होकर गुजरती है, जो भारत की जमीन है और चीन का वहां अवैध कब्जा है। भारत अपने प्रमुख साझेदार देशों के साथ आतंकवाद, सीमा-पार आतंकवाद, क्षेत्रीय स्थिरता और नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था जैसे मुद्दों पर सहयोग बढ़ाकर अपनी रणनीतिक स्थिति को और सुदृढ़ कर सकता है।

भारत की नीति का आधार संयम, कूटनीतिक सक्रियता, राष्ट्रीय सुरक्षा की तैयारी और क्षेत्रीय स्थिरता होना चाहिए। पीओके में विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं और आकांक्षाएं मौजूद हैं। इसलिए भारत के लिए सबसे प्रभावी रणनीति यह होगी कि वह लोकतांत्रिक मूल्यों, विकास, सुशासन और संवैधानिक व्यवस्था की अपनी उपलब्धियों को सशक्त रूप से प्रस्तुत करे तथा कूटनीतिक स्तर पर अपने दावों और हितों को तथ्य एवं अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप आगे बढ़ाए।

बलूचिस्तान में जारी असंतोष, मानवाधिकार संबंधी चिंताएं तथा राजनीतिक अस्थिरता भारत के लिए अपनी कूटनीतिक सक्रियता और वैश्विक विश्वसनीयता को मजबूत करने का अवसर प्रदान करती है। भारत लंबे समय से आतंकवाद के खात्मे, क्षेत्रीय स्थिरता और लोकतांत्रिक मूल्यों की वकालत करता रहा है। किसी भी बहु-जातीय और बहुभाषी समाज में दीर्घकालिक स्थिरता केवल सैन्य उपायों से नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक भागीदारी, संवैधानिक अधिकारों, न्यायपूर्ण प्रशासन और समावेशी विकास से सुनिश्चित होती है।

पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही से लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थाओं की रिपोर्ट और संयुक्त राष्ट्र में बलूचिस्तान में गुमशुदगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर चिंता सामने आई है। भारत इन विषयों पर सिद्धांत आधारित और तथ्यपरक दृष्टिकोण अपनाते हुए अपनी कूटनीतिक स्थिति स्पष्ट कर सकता है। इससे भारत की यह छवि मजबूत होगी कि वह मानवाधिकारों और लोकतांत्रिक मूल्यों को महत्त्व देता है।

रणनीतिक तकाजा: बलूचिस्तान की अस्थिरता यह दर्शाती है कि केवल सैन्य दृष्टिकोण से जटिल राजनीतिक समस्याओं का स्थायी समाधान संभव नहीं है। भारत इस अनुभव के आधार पर आतंकवाद के खिलाफ व्यापक अंतरराष्ट्रीय सहयोग, कट्टरपंथ के विरुद्ध साझा रणनीति और क्षेत्रीय स्थिरता की आवश्यकता पर बल दे सकता है। चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे की सुरक्षा संबंधी चुनौतियां यह संकेत देती हैं कि बड़े अवसंरचनात्मक निवेश तभी सफल हो सकते हैं, जब स्थानीय समुदायों की भागीदारी और राजनीतिक स्वीकार्यता सुनिश्चित हो।

भारत अपने संपर्क और विकास संबंधी परियोजनाओं में स्थानीय भागीदारी, पारदर्शी शासन और साझेदारी-आधारित मॉडल को प्रमुखता देकर स्वयं को एक विश्वसनीय विकास साझेदार के रूप में प्रस्तुत कर सकता है। पाकिस्तान में दीर्घकालिक अस्थिरता का प्रभाव सीमा-पार सुरक्षा, आतंकवाद, शरणार्थी संकट और क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग पर भी पड़ सकता है। इसलिए भारत के हित में यही होगा कि वह मजबूत सीमा सुरक्षा, प्रभावी कूटनीति, वैश्विक साझेदारियों और लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन के माध्यम से अपनी स्थिति को सुदृढ़ करे।

भारत के लिए कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां: भारत के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण सावधानियां भी आवश्यक हैं। खैबर पख्तूनख्वा में अस्थिरता से आतंकवादी संगठनों की गतिविधियां बढ़ सकती हैं, जिनका प्रभाव पूरे दक्षिण एशिया की सुरक्षा पर पड़ सकता है। इसलिए भारत को सीमा सुरक्षा, आतंकवाद-रोधी सहयोग, खुफिया समन्वय तथा क्षेत्रीय कूटनीति को निरंतर मजबूत बनाए रखना होगा।

खैबर पख्तूनख्वा की जटिल परिस्थितियां, अफगानिस्तान के साथ इसके ऐतिहासिक और सामाजिक संबंध तथा पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियां भारत के लिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के साथ कूटनीतिक, रणनीतिक और क्षेत्रीय सहयोग के नए अवसर प्रस्तुत कर रही हैं। भारत की नीति परंपरागत रूप से क्षेत्रीय स्थिरता, आतंकवाद का विरोध और विकास में सहयोग पर केंद्रित रही है। इसलिए इन परिस्थितियों में वह अपनी रणनीति को और प्रभावी बना सकता है।

दीर्घकालिक दृष्टि से भारत के लिए सबसे बड़ी रणनीतिक बढ़त किसी पड़ोसी देश की आंतरिक कमजोरियों पर निर्भर नहीं होगी, बल्कि अपनी राष्ट्रीय शक्ति के सभी आयामों को निरंतर सुदृढ़ करने में निहित है। मजबूत अर्थव्यवस्था, तेज विकास, तकनीकी नवाचार, रक्षा आधुनिकीकरण, कुशल कूटनीति और विश्वसनीय लोकतांत्रिक संस्थाएं भारत की वास्तविक रणनीतिक पूंजी हैं।

भारत जब अपनी आर्थिक क्षमता, सैन्य प्रतिरोध शक्ति, कूटनीतिक प्रभाव और लोकतांत्रिक विश्वसनीयता को समान गति से आगे बढ़ाएगा, तब वह केवल दक्षिण एशिया ही नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति में भी अधिक प्रभावशाली और निर्णायक भूमिका निभाने की स्थिति में होगा।

इसलिए जरूरी है नाम बदलना

(डॉ. अवनीश मिश्रा)

कोई राष्ट्र यदि अपनी पहचान भुला देता है तो वह अपना गौरवबोध खोने के साथ ही भविष्य की दिशा भी खो देता है। कहते हैं कि जड़ों से कटा वृक्ष कभी छाया नहीं दे सकता। यही सत्य सभ्यताओं पर भी लागू होता है जिसकी पहचान नामों से होती है। नदी का नाम, नगर का नाम, गली-मोहल्ले का नाम, ये मात्र पहचान के चिह्न नहीं हैं, आस्था और सांस्कृतिक निरंतरता के जीवंत साक्षी भी हैं। भारत पर हमले के बाद आक्रांताओं ने इसीलिए यहां की पहचान को सबसे पहले बदलने का प्रयास किया। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश में कई स्थानों के नाम बदल दिए गए। उत्तर प्रदेश की पावन धरती ने लंबे समय तक इस सांस्कृतिक हिंसा को चुपचाप सहा लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सत्ता में आने के बाद से यह मौन टूटने लगा। उत्तर प्रदेश में गुलामी के प्रतीकों को हमेशा के लिए खत्म करने की दिशा उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए और कई स्थानों का नाम बदलकर उन्हें उनका गौरव वापस दिलाया। हाल ही में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम परशुराम पुरी, अयोध्या जिले में नगर पंचायत खिलौनी-सुचितगंज को मां ज्वाला जी, कुशीनगर के फाजिलनगर का पावागढ़ और भदरसा को भरत नगर करना सीओम योगी की इसी प्राथमिकता का हिस्सा हैं।

इतिहास को पलटने में कई काले पन्ने भी दिखते हैं। इन पन्नों में मुगलकाल में उत्तर प्रदेश के शहरों, गांवों और कस्बों का नाम बदला जाना भी है। गाजीपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, इलाहाबाद, फतेहपुर, फिरोजाबाद, शाहजहांपुर और मुजफ्फरनगर जैसे अनेक बड़े जिलों के नाम मुगल सल्तनतों, उनके सेनापतियों और परिजनों के नाम पर रखे गए। आगरा को अकबराबाद कहा गया, प्रयागराज को इलाहाबाद कर दिया गया। यह एक सुनियोजित सांस्कृतिक विस्थापन था, जिसने भारत की मूल पहचान पर आक्रांताओं की मुहर लगा दी। योगी सरकार इन नामों को बदलने का साहस दिखा रही है, तो यह केवल इतिहास का सुधार नहीं, बल्कि उस अन्याय का भी प्रतिकार है जो पीढ़ियों ने सहा।

इलाहाबाद का प्रयागराज बनना इस यात्रा का सबसे प्रतीकात्मक अध्याय है। जिस भूमि पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का पवित्र संगम होता है, जहां हर बारह वर्ष में करोड़ों श्रद्धालु कुंभ स्नान के लिए उमड़ते हैं, उस नगर को एक ऐसा नाम ढोना पड़ा जिसका उसकी आध्यात्मिक चेतना से कोई नाता नहीं था। योगी सरकार ने प्रयागराज को उसका पुराना नाम वापस दिया है तो मानों इस पौराणिक स्थल की आत्मा वापस आई है। इसी तरह फैजाबाद जिले का नाम बदलकर अयोध्या करना भगवान श्रीराम की जन्मभूमि को उसका वास्तविक गौरव लौटाने जैसा कदम है। मुगलसराय रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर करना भी इसी श्रृंखला की एक कड़ी है, जिसने एक महान विचारक को सम्मान देकर उस स्थान को नई पहचान दी।

हाल ही में शाहजहांपुर जिले की जलालाबाद तहसील का नाम बदलकर 'परशुराम पुरी' करने का निर्णय राज्य मंत्रिमंडल ने लिया तो इसके भी विशिष्ट कारण हैं। यह क्षेत्र भगवान परशुराम की जन्मस्थली के रूप में पौराणिक ग्रंथों में वर्णित है और स्थानीय जनता वर्षों से इस पुनर्स्थापना की मांग कर रही थी। इसी तरह अयोध्या में खिलौनी-सुचितगंज को 'मां ज्वाला' का नाम दिया जाना और भदरसा 'भरत नगर' की संज्ञा दिया जाना भी जन-आकांक्षाओं और लोक-आस्था का सम्मान है। गोरखपुर, जो स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कर्मभूमि है, वहां भी उन्होंने सांसद रहते हुए इसी दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए। उर्दू बाजार का नाम 'हिंदी बाजार', हुमायूंपुर का नाम 'हनुमान नगर', मियां बाजार का नाम 'माया बाजार' और अलीनगर का नाम 'आर्य नगर' कर दिया गया। ये सभी परिवर्तन स्थानीय पहचान को उसकी सांस्कृतिक जड़ों से पुनः जोड़ने का प्रयास हैं।

वस्तुतः सनातन आस्था से जुड़े लोग स्वयं भी गुलामी के प्रतीक इन नामों से मुक्ति चाहते हैं इसलिए उनकी ओर से इसके लिए आवाजें उठती रही हैं। संभल जिले के लिए कल्कि नगर या पृथ्वीराज नगर जैसे नाम सुझाए गए हैं, जो भगवान विष्णु के भावी अवतार और पृथ्वीराज चौहान जैसे शौर्यवान शासक की स्मृति को सम्मान देने का प्रयास हैं। देवबंद को देववृंदपुर करने की मांग भी स्थानीय जनप्रतिनिधि उठा चुके हैं। जब कोई समाज अपने नगरों को उनके पौराणिक, ऐतिहासिक या आस्था से जुड़े नामों से पुकारना चाहता है, तो लोकतांत्रिक सरकार का कर्तव्य है कि वह उस भावना को स्वर दे और योगी सरकार ने यही किया है।

आलोचक यह सवाल उठाते हैं कि नाम बदलने से आम आदमी के जीवन में क्या बदलाव आएगा ? यह तर्क कुतर्क है क्योंकि इसमें हमारी सांस्कृतिक स्मृति की अनदेखी होती है।

लोगों के घटते भरोसे के दौर में शायद देश को नई राजनीति और नए नेतृत्व की तलाश है

(तवलीन सिंह)

बहुत दिनों बाद दिल्ली आना हुआ पिछले सप्ताह। सीधे जंतर-मंतर गई। दोपहर का समय था और धूप इतनी तेज कि बिना सिर ढके खड़ा होना मुश्किल था। गाड़ी को थोड़ी दूर खड़ी करके मैं पैदल चली। दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई थीं और प्रदर्शनकारियों को देखने से पहले दिखे पुलिसवाले इतने सारे कि जैसे जमा होते हैं तब, जब गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। मेटल डिटेक्टर से जब गुजरी, तो देखा कि सड़क के दोनों तरफ प्लास्टिक की बोतलें और अलग किस्म का कूड़ा पड़ा हुआ था। थोड़ा आगे गई, तो देखा कि वामपंथी दलों के विद्यार्थी संगठनों के कार्यकर्ता बैठे हुए थे।

काकरोच जनता पार्टी पैदा हुई है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, ताकि कभी न कभी प्रधानमंत्री के दफ्तर तक संदेश पहुंचे कि शिक्षा क्षेत्र में जो खराबी आई है, उसकी जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है। प्रदर्शन कर रही भीड़ की पृष्ठभूमि पर बड़े अक्षरों में लिखा घटते भरोसे के बीच, जो व्यवस्था, जवाबदेही और जनविश्वास पर उठते सवालों का सांकेतिक चित्रण करता है।

बहुत दिनों बाद दिल्ली आना हुआ पिछले सप्ताह। सीधे जंतर-मंतर गई। दोपहर का समय था और धूप इतनी तेज कि बिना सिर ढके खड़ा होना मुश्किल था। गाड़ी को थोड़ी दूर खड़ी करके मैं पैदल चली। दोनों तरफ गाड़ियां लगी हुई थीं और प्रदर्शनकारियों को देखने से पहले दिखे पुलिसवाले इतने सारे कि जैसे जमा होते हैं तब, जब गड़बड़ी होने की आशंका रहती है। मेटल डिटेक्टर से जब गुजरी, तो देखा कि सड़क के दोनों तरफ प्लास्टिक की बोतलें और अलग किस्म का कूड़ा पड़ा हुआ था। थोड़ा आगे गई, तो देखा कि वामपंथी दलों के विद्यार्थी संगठनों के कार्यकर्ता बैठे हुए थे।

थोड़ा और आगे गई, तो देखा कि मंच के सामने एक आदमी भाषण दे रहा था उस किस्म का जैसे मामूली कार्यकर्ता देते हैं नेताओं के मंच पर आने से पहले। मंच पर काकरोच जनता पार्टी के कुछ नेता बैठे हुए थे, लेकिन अभिजीत दिपके नहीं दिखे। यह सोच ही रही थी कि मेरे साथ खड़े हुए एक आदमी ने कहा कि 'वे आ रहे हैं'। 'वे' दिपके थे जो अति-विनम्रता से सब लोगों के हाथ पकड़ कर आगे बढ़ रहे थे, जैसे उनको धन्यवाद कहना चाह रहे हों। मुझ तक पहुंचे, तो मैंने नमस्ते करना चाहा, लेकिन उन्होंने हाथ मिलाया। उनके चेहरे पर हल्की-सी मुस्कुराहट थी और थोड़ा आश्चर्य, तो मैंने उनको कहा कि मैं एक पत्रकार हूं।

दिपके आगे बढ़े, तो मेरे बगल में खड़े एक आदमी ने कहा, 'मुझे मालूम था कि आप पत्रकार हैं।' यह आदमी कोई चालीस साल का था। मैंने उससे पूछा कि वह कहां से आया है और किस वास्ते, तो उसका जवाब यह था, 'मैं नोएडा में रहता हूं और जबसे यह प्रदर्शन शुरू हुआ है, मैं यहां रोज आता हूं समर्थन जताने। ये लोग अच्छा कर रहे हैं देश के लिए।'

इतने में मुझे दो-तीन नौजवान दिखे, जिन्होंने बताया कि वे आजमगढ़ से आए हैं समर्थन जताने इसलिए कि उनके कुछ दोस्त हैं जो पर्चा लीक होने के शिकार रहे हैं। आसपास कोई इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जो लोग मिले, वे सब अपनी मर्जी से आए थे किसी राजनीतिक दल के कहने पर नहीं आए थे।

यहां स्पष्ट करना जरूरी है कि मैं सोनम वांगचुक की इज्जत करती हूं और उनको राष्ट्रविरोधी बिल्कुल नहीं मानती हूं, लेकिन उनके आमरण अनशन से सहमत नहीं हूं। इस किस्म के सत्याग्रह मुझे पसंद नहीं हैं। मैं मानती हूं कि ऐसे आमरण अनशन से सरकार पर दबाव डालना गलत है और बेमतलब भी। मगर जिस वजह से काकरोच जनता पार्टी बनी है, उसका मैं दिल से समर्थन करती हूं।

जब जनता के चुने हुए जनसेवक बहरे हो जाते हैं, तो उन तक अपनी आवाज को पहुंचाना मुश्किल होता है। काकरोच जनता पार्टी पैदा हुई है अपनी आवाज बुलंद करने के लिए, ताकि कभी न कभी प्रधानमंत्री के दफ्तर तक संदेश पहुंचे कि शिक्षा क्षेत्र में जो खराबी आई है, उसकी जवाबदेही शिक्षा मंत्री की है। कुछ और नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम इस्तीफा तो दे सकते हैं।

संयोग से पिछले सप्ताह यही बात एक मोदी भक्त से कहने का मुझे अवसर मिला। यह व्यक्ति न पत्रकार है न राजनीतिक, लेकिन दिल्ली के ऊंचे गलियारों में घूमता है, इसलिए जानता है अच्छी तरह कि उनमें चर्चा क्या हो रही है। मैंने जब धर्मेंद्र प्रधान की जवाबदेही का उससे जिक्र किया, तो उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रधानमंत्री का पक्का इरादा था अपने चहेते मंत्री को बर्खास्त करने का, लेकिन जब काकरोच जनता पार्टी ने अपना प्रदर्शन शुरू किया, तो इस काम को उन्हें रोकना पड़ा इसलिए कि भारत के प्रधानमंत्री को कभी दबाव पड़ने की वजह से फैसले नहीं लेने चाहिए।

इस व्यक्ति ने मुझे कहा कि इस नई पार्टी के तमाम नेता आम आदमी पार्टी से निकल कर आए हैं और अरविंद केजरीवाल का आशीर्वाद लेकर अपना काम कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कई नेता दिखे भी हैं मंच पर, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि 'आप' से प्रेरणा लेकर प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। यह बात उनके खिलाफ रही है अभी से। केजरीवाल की छवि इतनी बिगड़ी हुई है कि जब भी किसी को लगता है कि उनके कहने पर कुछ हो रहा है, तो लोग फौरन अपना समर्थन वापस ले लेते हैं।

केजरीवाल को पहली बार मैंने देखा था अस्सी घाट पर। बटवृक्ष के नीचे बैठे हुए 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान। ये वे दिन थे, जब उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देकर नरेंद्र मोदी को चुनौती देने का गलत निर्णय लिया था। मुझे उस वक्त से लगा था कि आम आदमी के चोले के नीचे यह एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आपको इतना खास समझता है कि मुख्यमंत्री बनते ही प्रधानमंत्री बन जाने के सपने देखने लग गया है।

काकरोच जनता पार्टी अगर बनना चाहती है देश के नौजवानों की आवाज, तो उसको विनम्रता से मेरा सुझाव यह है कि केजरीवाल से दूर रहें और वामपंथी राजनेताओं तथा राजनीतिक दलों से भी। ये ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज फीकी पड़ चुकी है। आम लोग जान गए हैं कि ये लोग बातें तो बड़ी-बड़ी करते हैं, लेकिन जमीन पर उनका काम इतना बेकार साबित हुआ है कि आम लोगों का इनमें अब कोई विश्वास नहीं रहा। नौजवानों को नए नेता ढूंढने होंगे अगर वास्तव में वह देश में बदलाव लाना चाहते हैं। समस्या सिर्फ शिक्षा क्षेत्र में नहीं है, हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार इतना फैला हुआ है आज कि मोदी सरकार में भी भरोसा कम होने लग गया है। असली परिवर्तन के लिए नए लोग चाहिए। नई सोच चाहिए।

संक्षिप्त समाचार

भाजपा विधायक का कांग्रेस पर हमला, बोले- 'भारत माता का सम्मान करने वाला ही करेगा राज'

रायपुर। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम के अपमान या इसे गाने में बाधा डालने को आपराधिक अपराध बनाने संबंधी प्रस्तावित विधेयक को लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस मुद्दे पर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला।पुरंदर मिश्रा ने कहा कि जो भारत माता का सम्मान करेगा, वही इस देश में राज करेगा। कांग्रेस यदि 'भारत माता की जय' नहीं बोलना चाहती तो उसे भारत में रहने का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस को चीन या इटली चले जाना चाहिए।बिजली बिल अभियान पर भी साधा निशानाकांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे बिजली बिल अभियान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक ने कहा कि जनता को लूटने का काम पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किया था। उन्होंने आरोप लगाया कि बिजली बिल से जुड़े ठेकों का काम कांग्रेस शासनकाल में केवल तीन कंपनियों को दिया गया था और इसकी जांच होनी चाहिए।उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब जनता के बीच जाकर वर्तमान विष्णुदेव साय सरकार की छवि खराब करने की कोशिश कर रही है, जबकि बिजली बिल से जुड़ी गड़बड़ियों की जिम्मेदारी पूर्ववर्ती सरकार की है।भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के दौरे पर तंजपूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लगातार संयुक्त दौरों पर भी पुरंदर मिश्रा ने कटाक्ष किया। उन्होंने कहा, 2018 में हनीमून की सरकार बनी थी, फिर उनका तलाक हो गया। अब एक बार फिर दोनों हनीमून मना रहे हैं।भाजपा विधायक के इन बयानों के बाद प्रदेश की राजनीति में बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं।

राजधानी में दिनदहाड़े कारोबारी पर जानलेवा हमला सोने की चेन लूटकर फरार

रायपुर। राजधानी रायपुर के न्यू राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े मारपीट और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। लालपुर ब्रिज के नीचे कुछ बदमाशों ने पहले एक कारोबारी की कार पर पत्थर मारकर पीछे का शीशा तोड़ दिया। जैसे ही कारोबारी कार से बाहर निकला, आरोपियों ने डंडे, सरिया और हथौड़े से उस पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि बीच-बचाव करने पहुंचे कारोबारी के साथियों के साथ भी आरोपियों ने मारपीट की। इस दौरान बदमाश कारोबारी के गले से सोने की चेन लूटकर मौके से फरार हो गए। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो के आधार पर न्यू राजेंद्र नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर उनकी तलाश कर रही है।

महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म, तीन अज्ञात ट्रक चालकों पर केस दर्ज

रायपुर । छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में एक महिला के साथ कथित सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म का मामला दर्ज कर तीन अज्ञात आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है।जानकारी के अनुसार, कांकेर जिले की रहने वाली महिला बालोद-दल्ली राजहरा मुख्य मार्ग स्थित पर्यावरण पार्क के पास बेसुध अवस्था में मिली थी। स्थानीय लोगों की सूचना पर डायल-112 की टीम मौके पर पहुंची और महिला को उपचार के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में होश आने के बाद महिला ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि उसका अपहरण कर तीन लोगों ने उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। महिला के बयान के आधार पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।प्रारंभिक जांच में आशंका जताई जा रही है कि घटना में तीन अज्ञात ट्रक चालक शामिल हो सकते हैं। हालांकि, पुलिस ने अभी आरोपियों की आधिकारिक पहचान की पुष्टि नहीं की है और मामले की विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मोनिका ठाकुर ने बताया कि पीड़िता कांकेर जिले की निवासी है।

नगर निगम लाईसेंस फीस का बकाया भुगतान नहीं करने पर 14 दुकानों को सीलबंद करने की कार्रवाई

रायपुर। रायपुर अबटीम प्रहरी अभियान अंतर्गत रायपुर पुलिस कमिश्नर संजीव शुक्ला और रायपुर जिला कलेक्टर डॉ गौरव कुमार सिंह के आदेशानुसार और नगर निगम आयुक्त संबित मिश्रा के निर्देशानुसार नगर निगम मुख्यालय भवन महात्मा गांधी सदन के सामने नगर निगम उद्यान परिसर में नगर निगम उद्यान विभाग की टीम ने नगर निगम मुख्यालय नगर निवेश उडनदस्ता की टीम के सहयोग से वहां स्थित 14 दुकानों द्वारा नगर निगम लाईसेस फीस का बकाया भुगतान नहीं करने पर सीलबंद करने की कार्यवाही उपायुक्त उद्यान जागृति साहू के मार्ग निर्देशन एवं उप अभियंता उद्यान रूचिका मिश्रा की उपस्थिति में की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर निगम मुख्यालय भवन के सामने निगम उद्यान परिसर में गणपति इंप्रा को 14 दुकानें 5 वर्ष के लिए संचालित करने का लाईसेंस दिया गया है, जो अगस्त 2026 को समाप्त हो रहा है।

सीसीटीएनएस को और सशक्त बनाने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक

ई-साक्ष्य के लिए सभी जिलों में विशेष प्रशिक्षण अभियान चलेगा

- स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडलीपार द्वारा जांच प्रकिया को त्वरित करने दिए निर्देश
- नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप न्याय प्रक्रिया को त्वरित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर

रायपुर/ संवाददाता

छत्तीसगढ़ में नवीन भारतीय न्याय संहिता के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय प्रक्रिया को तकनीक आधारित, सरल एवं त्वरित बनाने की दिशा में उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री श्री विजय शर्मा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंगलवार को क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रेकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम (सीसीटीएनएस) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक ली। बैठक में सीसीटीएनएस के संचालन में आ रही व्यवहारिक चुनौतियों, विभिन्न डिजिटल मॉड्यूल के एकीकरण तथा न्यायिक एवं पुलिस व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप अपराधों की विवेचना, साक्ष्य संकलन, न्यायालयीन प्रक्रिया तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वय को पूर्णत: डिजिटल और समयबद्ध बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने निर्देश दिए कि सीसीटीएनएस के माध्यम से न्याय प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को अधिक सुगम, पारदर्शी और नागरिक हितैषी बनाया जाए। बैठक में ई-एफआईआर, ई-चालान, ई-साक्ष्य, मेडलीपार, ई-प्रिजन, ई-फोरेंसिक, सीआईएस, न्याय श्रुति तथा अन्य डिजिटल प्रणालियों को सीसीटीएनएस के साथ प्रभावी रूप से संचालित करने पर विस्तार से चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन सभी मॉड्यूलों के बीच समन्वय स्थापित कर न्याय

प्रक्रिया को अधिक तेज और पारदर्शी बनाया जाए, जिससे नागरिकों को त्वरित न्याय उपलब्ध हो सके। श्री शर्मा ने कहा कि डिजिटल साक्ष्यों का महत्व लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि राज्य के सभी जिलों में पुलिस अधिकारियों एवं संबंधित कर्मचारियों को ई-साक्ष्य प्रणाली का व्यापक प्रशिक्षण दिया जाए, ताकि डिजिटल साक्ष्यों का संकलन, संरक्षण एवं न्यायालय में प्रस्तुतिकरण पूरी दक्षता के साथ किया जा सके। उन्होंने अच्छा कार्य करें वाले जिलों को प्रोत्साहित कर उन बैठक में न्याय श्रुति प्रणाली को शीघ्र प्रारंभ करने पर भी चर्चा हुई। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि उच्च न्यायालय के माध्यम से सभी न्यायाधीशों की आवश्यक आईडी तैयार कराकर न्याय श्रुति प्रणाली को जल्द से जल्द गो-लाइव किया जाए, जिससे न्यायालयीन प्रक्रियाओं में तकनीक का अधिक प्रभावी उपयोग सुनिश्चित हो सके। बैठक में प्रार्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रारंभिक चरण में दुर्ग, बिलासपुर तथा रायपुर कमिश्नरेट के सभी थानों में तथा राज्य के प्रत्येक जिले के दो-दो थानों में इस माह के अंत तक दो-दो ई-साइनिंग पैड उपलब्ध कराए जाएं। इससे शिकायतकर्ताओं के डिजिटल हस्ताक्षर की प्रक्रिया सरल होगी और दस्तावेजों का ऑनलाइन निष्पादन अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगा। इसके बाद पूरे राज्य में सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। श्री शर्मा ने नवीन भारतीय न्याय संहिता के अनुरूप न्याय व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के सभी पांचों स्तंभों को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस, न्यायालय, जेल, फोरेंसिक तथा अभियोजन तंत्र के बीच बेहतर समन्वय स्थापित कर न्याय प्रक्रिया को समयबद्ध बनाया जाए।बैठक में स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मेडिकल जांच एवं रिपोर्ट की प्रक्रिया को और तेज बनाने के लिए हरसंभव सहयोग का आश्वासन दिया।

वृक्षारोपण केवल अभियान नहीं सुरक्षित भविष्य का संकल्प है....

रायपुर। संवाददाता

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल आज सरगुजा जिले के लखनपुर स्थित जी.आर.ए. स्कूल, जूनाडीह में आयोजित वृक्षारोपण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने विद्यालय परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और उपस्थित जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर हरित एवं स्वच्छ भविष्य के निर्माण का संकल्प लिया।इस अवसर पर पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री राजेश अग्रवाल ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। पर्यावरण संरक्षण केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। आज लगाया गया एक पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वच्छ हवा, हरियाली और सुरक्षित भविष्य की अमूल्य धरोहर बनता है। उन्होंने सभी नागरिकों से अधिक से अधिक वृक्ष लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का आग्रह किया।श्री अग्रवाल ने अपने संबोधन में आगे कहा कि वृक्ष केवल पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने का माध्यम नहीं हैं, बल्कि मानव जीवन के आधार हैं। जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण की वर्तमान आवश्यकता को देखते हुए प्रत्येक व्यक्ति को पौधारोपण को जनआंदोलन बनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि पौधा लगाना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं अधिक आवश्यक उसकी नियमित देखभाल करना है, ताकि वह एक सशक्त वृक्ष बनकर समाज और प्रकृति की सेवा कर सके।उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद करते हुए कहा कि युवा पीढ़ी पर्यावरण संरक्षण की सबसे बड़ी शक्ति है। यदि विद्यार्थी अपने जीवन में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता विकसित करेंगे और प्रत्येक वर्ष कम से कम एक पौधा लगाकर उसकी देखभाल करेंगे, तो आने वाले वर्षों में पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उल्लेखनीय परिवर्तन देखने को मिलेगा। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रकृति से जुड़ने, पर्यावरण के प्रति जागरूक रहने तथा जीवन में अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के साथ निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया।

करंट लगने से किसान की मौत, खेत में सिंचाई के दौरान हुआ हादसा

रायपुर । छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में करंट लगने से एक किसान की मौत हो गई। यह दर्दनाक हादसा बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम झरगांव में हुआ, जहां धान की सिंचाई के दौरान 41 वर्षीय किसान रतन पैंकरा बिजली की चपेट में आ गए।प्राप्त जानकारी के अनुसार, खेत में मोटर पंप चलाने के लिए कथित तौर पर अवैध बिजली हुकिंग की गई थी। इसी दौरान किसान नंगे बिजली के तार के संपर्क में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई।बताया जा रहा है कि किसान देर रात तक घर नहीं लौटे, जिसके बाद परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन दोपहर उनका शव खेत में मिला। घटना की सूचना मिलने पर बतौली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की

मुख्य सचिव विकासशील ने विभागी सचिवों की ली उच्च स्तरीय बैठक....

रायपुर/ संवाददाता

मुख्य सचिव श्री विकासशील ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन में राज्य शासन के समस्त विभागों के भार सादक सचिवों की बैठक ली। बैठक में विभागों के महत्वपूर्ण कार्यों एवं योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने कहा है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी-कर्मचारियों के विभिन्न प्रकरणों के निराकरण की प्रक्रिया दो वर्ष से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए है कि सेवा निवृत्त होने वाले अधिकारी कर्मचारियों की सूची विभागावार अद्यतन कर ली जाए। मुख्य सचिव ने विभागीय सचिवों को उनके विभाग की योजनाओं के क्रियान्वयन एवं प्रगति की लगातार मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए है। बैठक में ई-ऑफिस, आधार बेस अटेंडेंस, लोक सेवा गारंटी, सूचना के अधिकार, सुघ्घर छत्तीसगढ़, नियद नेल्लानार योजना, पीएम प्रगति पोर्टल, ई-प्रगति, डी रेगुलेशन ई-गजट, सेवा सेतु, ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं, पीएम सूर्य घर बिजली सहित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं की प्रगति के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई। मुख्य सचिव ने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि आई-गॉट के तहत विभागवार चिन्हित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग की जाये। अधिकारी-कर्मचारियों को आई-गॉट के तहत विभाग की आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण दिलाने कहा है। मुख्य सचिव ने कहा है कि सभी विभागों की योजनाओं एवं सेवाओं को ऑनलाइन किया जाए। बैठक में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार पिंगुआ, गृह एवं जेल विभाग की प्रमुख सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह, आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा।

अवैध हथियार,गांजा और शराब के मामलों में कई एफआईआर दर्ज....

रायपुर। संवाददाता

राजधानी रायपुर में विभिन्न थाना क्षेत्रों में चोरी, मारपीट, सड़क हादसे, अवैध हथियार, मादक पदार्थ और आबकारी अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। तेलीबांधा थाना क्षेत्र के सूरज नगर, लभांडी से प्रीतम यादव की खड़ी मोटरसाइकिल (सीजी-04-एनआर-8126) अज्ञात चोर चोरी कर ले गया। पुलिस ने करीब 30 हजार रुपये की चोरी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उरला थाना क्षेत्र के शांतिनगर बीरगांव में आपसी विवाद को लेकर दो पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। नेहा दुबे की शिकायत पर मुकेश यादव एवं अन्य के खिलाफ तथा मुकेश यादव की शिकायत पर नेहा दुबे एवं अन्य के खिलाफगाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में अपराध दर्ज किया गया है। आजाद चौक थाना क्षेत्र में साइकिल वापस मांगने को लेकर हुए विवाद में लक्ष्मीनारायण यादव के साथ मारपीट कर घायल करने का मामला दर्ज हुआ है। वहीं राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में लालपुर ब्रिज के नीचे कार का शीशा पत्थर मारकर तोड़ने, मारपीट और धमकी देने के आरोप में राम कोलरिया एवं अन्य के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया है। डीडी नगर थाना क्षेत्र में स्कूटी टकराने के बाद हुए विवाद में भी युवक के साथ मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में विधानसभा रोड स्थित माता गैरेज के सामने हुए सड़क हादसे में घायल सुंदरलाल माहेश्वरी की उपचार के दौरान मौत हो गई। मर्ग जांच के बाद अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाकर मृत्यु कारित करने का अपराध दर्ज किया गया है। खम्हारडीह थाना क्षेत्र के अवंति विहार स्थित एक मकान में अज्ञात चोर घर में घुसकर 18,500 रुपये कीमत का सैमसंग मोबाइल चोरी कर ले गया। वहीं खमतराई थाना क्षेत्र में शराब के नशे में बेटे द्वारा अपनी मां के साथ गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी और बेलन से हमला कर घायल करने का मामला दर्ज किया गया है। गंज थाना पुलिस ने बांसटाल पानी टंकी के पास कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 17 पाव देशी शराब और बिक्री रकम के साथ गिरफ्तार किया है। कोतवाली थाना पुलिस ने अलग-अलग स्थानों पर दो 17 वर्षीय अपचारी बालकों को अवैध चाकू लेकर लोगों को आतंकित करते हुए पकड़कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है।

भूपेश-टीएस के संयुक्त दौरों पर भाजपा का तंज,यूसीसी और विकास कार्यों पर भी कांग्रेस को घेरा

रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजनीति में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पूर्व उपमुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के लगातार संयुक्त दौरों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। मंत्री रामविचार नेताम और भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने इस मुद्दे पर तंज कसते हुए कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति पर भी टिप्पणी की। रामविचार नेताम ने कहा, बाबा को भेलपुरी खिला रहे हैं, नट-बोल्ट वाले कड़कनाथ भी खिलाएं। दिल मिले या न मिले, आंखें जरूर मिला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसे प्रदेश अध्यक्ष बनाए या किसे राष्ट्रीय स्तर पर जिम्मेदारी दे, यह पूरी तरह उस पार्टी का आंतरिक मामला है। वहीं भाजपा विधायक पुरंदर मिश्रा ने कटाक्ष करते हुए कहा, 2018 में हनीमून की सरकार बनी थी, फिर उनका तलाक हो गया। अब एक बार फिर दोनों हनीमून मना रहे हैं। समान नागरिक संहिता ष्टष्ट को लेकर मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि कांग्रेस लोगों के बीच भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि ष्टष्ट से आदिवासी, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अधिकार या आरक्षण पर कोई असर नहीं पड़ेगा।उन्होंने कहा कि कांग्रेस राजनीतिक लाभ के लिए लोगों को गुमराह कर रही है, जबकि सरकार स्पष्ट कर चुकी है।

बिहान की दीदियों ने बदली तकदीर, ईंट निर्माण से बनीं आत्मनिर्भर'

- 5,500 ईंटें बेचकर कमाए 1.32 लाख रुपये, अब बच्चों की पढ़ाई और परिवार की जिम्मेदारी खुद उठा रहीं महिलाएं

रायपुर/ संवाददाता

सुकमा जिले के कोंटा विकासखंड के दूरस्थ वनांचल ग्राम जीरमपाल की महिलाओं ने मेहनत, एकजुटता और सरकारी सहयोग से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत गठित बम्लेश्वर स्व-सहायता समूह की महिलाओं ने ईंट निर्माण का कार्य शुरू कर अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बनाई है। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी शिबहानश् योजना के तहत समूह को समय पर वित्तीय और तकनीकी सहायता मिली। जिला प्रशासन के मार्गदर्शन और महिलाओं की मेहनत से यह पहल सफल हुई। आज यह समूह ग्रामीण महिलाओं के लिए स्वरोजगार का प्रेरणादायी उदाहरण बन गया है। समूह की 10 महिलाओं ने मिलकर पिछले एक वर्ष में 5,500 ईंटों का निर्माण और विक्रय किया। इससे उन्हें 1 लाख 32 हजार रुपये की आय हुई। इस आय ने महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया और परिवार की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। समूह की सदस्य आसमती बताती हैं कि पहले छोटी-छोटी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता था। आज वे अपनी आय से बच्चों की पढ़ाई, कपड़े और घर की अन्य जरूरतें पूरी कर रही हैं। अब परिवार के निर्णयों में भी उनकी महत्वपूर्ण भागीदारी है। आत्मनिर्भर बनने से उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। बम्लेश्वर स्व-सहायता समूह की सफलता से जीरमपाल और आसपास के गांवों की अन्य महिलाएं भी स्वरोजगार से जुड़ने के लिए प्रेरित हो रही हैं। यह पहल नक्सल प्रभावित और दूरस्थ क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण तथा ग्रामीण आजीविका को मजबूत करने का सफल उदाहरण बनकर उभरी है। जीरमपाल की महिलाओं ने यह साबित कर दिया है कि यदि सही मार्गदर्शन, सरकारी योजनाओं का सहयोग और मेहनत का साथ मिले, तो ग्रामीण महिलाएं न केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति बदल सकती हैं, बल्कि पूरे गांव के विकास की नई कहानी भी लिख सकती हैं। श्बिहानश् योजना उनके सपनों को नई उड़ान देने का सशक्त माध्यम बन रही है।

हर माह बढ़ रही बचत,घर का बिजली बिल शून्य

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना बनी हरित समृद्धि की नई पहचान.....

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने, घरों में बिजली व्यय को कम करने तथा ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही है। यह योजना न केवल परिवारों को बिजली बिल से राहत प्रदान कर रही है, बल्कि अक्षय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। योजना के माध्यम से हजारों परिवार आर्थिक बचत के साथ हरित ऊर्जा को

अपनाकर स्वावलंबन की नई मिसाल स्थापित कर रहे हैं। कोरबा शहर के पत्थरीपारा की श्रीमती लारा तिर्की एवं उनके पति श्री अनजुलस तिर्की का परिवार भी प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना से लाभान्वित होकर सौर ऊर्जा के सकारात्मक परिणामों का अनुभव कर रहा है। योजना की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने अपने घर पर तीन किलोवाट क्षमता का सोलर रूफटॉप पैनल स्थापित कराया। सितम्बर-2025 में सोलर प्लांट लगने के बाद से उनके घर का बिजली बिल पूरी तरह समाप्त हो गया है और तब से अब तक उनका बिजली बिल लगातार शून्य आ रहा है। पहले उनके परिवार को प्रतिमाह लगभग एक हजार से डेढ़ हजार रुपये तक बिजली बिल का भुगतान करना पड़ता था, लेकिन अब यह राशि पूरी तरह बच रही है। श्रीमती तिर्की ने बताया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार से कुल एक लाख 8 हजार रुपये की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर प्लांट स्थापित करना उनके लिए आसान हो गया और किसी प्रकार की आर्थिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि यह योजना आम परिवारों के लिए अत्यंत लाभकारी है, क्योंकि इससे बिजली बिल से राहत मिलने के साथ-साथ स्वच्छ एवं अक्षय ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ा है।

संक्षिप्त समाचार

पटवारी निलंबित :राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी करने का मामला

रायपुर। बेमेतरा जिले के ग्राम निनवा के पटवारी हल्का क्रमांक-40 की पटवारी श्रीमती अम्बा उपाध्याय को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। कलेक्टर के निर्देश पर निलंबन की यह कार्रवाई राजस्व रिकॉर्ड में कथित अनियमित फेरबदल के मामले में की गई है। अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बेमेतरा की जांच में सामने आया कि निलंबित पटवारी द्वारा निजी स्वामित्व वाली भूमि के खसरा क्रमांक 184/1 एवं 184/2 के राजस्व अभिलेख और नक्शे में सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना बदलाव किया गया। यह कृत्य छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 115 एवं 116 के प्रावधानों के विपरीत किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9 के तहत पटवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। प्रशासन ने राजस्व कार्यों की निरंतरता बनाए रखने के लिए पटवारी हल्का क्रमांक-40 का अतिरिक्त प्रभार हल्का क्रमांक-26 के पटवारी श्री मेघनाथ वर्मा को सौंप दिया है।

रायपुर में अपराध पर पुलिस की कार्रवाई, मारपीट-धमकी से लेकर चोरी और नशीली टैबलेट बरामदगी के मामले दर्ज

रायपुर। राजधानी रायपुर में अलग-अलग थाना क्षेत्रों में बीते दिनों मारपीट, गाली-गलौज, जान से मारने की धमकी, चोरी, अवैध चाकू रखने और नशीली दवाओं की तस्करी से जुड़े कई मामले सामने आए। पुलिस ने विभिन्न मामलों में अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खमतराई थाना: धनलक्ष्मी नगर स्थित कृष्णा स्कूल के पास उधार पैसे के लेन-देन को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपियों ने प्रार्थी से गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी और हाथ-मुक्के से मारपीट करने के साथ उसकी स्कूटी की हेडलाइट तोड़ दी। पुरानी बस्ती थाना: कुशालपुर क्षेत्र में एक व्यक्ति और उसके साले के साथ बिना कारण गाली-गलौज और मारपीट कर जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। कबीर नगर थाना: हीरापुर में पारिवारिक मामले में दखल देने की बात को लेकर विवाद हुआ। आरोप है कि आरोपी ने महिला से गाली-गलौज कर धमकी दी और मारपीट कर चोट पहुंचाई। टिकरापारा थाना: गोकुल नगर रोड स्थित शराब दुकान के पास अज्ञात दो युवकों द्वारा एक व्यक्ति से गाली-गलौज, मारपीट और जान से मारने की धमकी देने की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया है। मोवा थाना: बालाजी मेडिकल कॉलेज के कैंपस में घुसकर अज्ञात दो आरोपियों द्वारा एसी के आउटडोर यूनिट में लगे करीब 10 हजार रुपये कीमत के कॉपर पाइप चोरी करने का मामला सामने आया है।

प्रयोगशाला परिचालक भर्ती परीक्षा 26 जुलाई को, 16 हजार से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल

रायपुर। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मण्डल, रायपुर द्वारा आयोजित प्रयोगशाला परिचालक के रिक्त पदों पर लिखित भर्ती परीक्षा (पीएसएलए-26) का आयोजन 26 जुलाई 2026 (रविवार) को जिले के 52 परीक्षा केंद्रों में किया जाएगा। परीक्षा प्रातः 10:00 बजे से 12:15 बजे तक आयोजित होगी। इस संबंध में कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार कलेक्ट्रेट परिसर स्थित रेडक्रॉस सोसायटी सभाकक्ष में ब्रीफिंग मीटिंग आयोजित की गई। परीक्षा के सुचारु एवं व्यवस्थित संचालन के लिए डिप्टी कलेक्टर उत्तम प्रसाद रजक को नोडल अधिकारी तथा विशेष रोजगार कार्यालय, रायपुर के रोजगार अधिकारी केदारनाथ पटेल को सहायक नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। परीक्षा में कुल 16 हजार 987 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा से संबंधित गोपनीय सामग्री का वितरण 26 जुलाई को प्रातः 6:00 बजे जिला कोषालय, कलेक्टर परिसर, रायपुर से किया जाएगा। नोडल अधिकारी ने परीक्षा के शांतिपूर्ण संचालन के लिए सभी पर्यवेक्षकों तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।

प्रोजेक्ट पाई-पाई के तहत वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में संचालित प्रोजेक्ट पाई-पाई के तहत भारतीय रिजर्व बैंक, नवा रायपुर के नेतृत्व में कृष्णा इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल, धनलक्ष्मी नगर, भनपुरी में आज वित्तीय साक्षरता जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्र-छात्राओं एवं शिक्षकों को बैंकिंग सेवाओं, वित्तीय प्रबंधन तथा सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के प्रति जागरूक करना था। कार्यक्रम में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को बैंकिंग योजनाओं, बजट निर्माण, बचत एवं निवेश के महत्व की जानकारी दी गई। साथ ही डिजिटल अरेस्ट, साइबर फ्रॉड एवं ऑनलाइन ठगी जैसे बढ़ते साइबर अपराधों से बचाव के उपायों के बारे में भी बताया गया। विशेषज्ञों ने कहा कि वर्तमान समय में साइबर अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को सतर्क रहकर सुरक्षित बैंकिंग व्यवहार अपनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल

स्वस्थ बच्चे और कुपोषण मुक्त छत्तीसगढ़ के लिए बनेगी रणनीति

- यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से सभी संबंधित विभाग मिलकर तैयार करेंगे प्रभावी कार्ययोजना
- स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव

रायपुर/ संवाददाता

मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से आज मंत्रालय महानदी भवन में भारत में यूनिसेफ की प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, कुपोषण उन्मूलन तथा बच्चों के समग्र विकास को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य तथा बच्चों के पोषण को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है और इन क्षेत्रों में स्थायी सुधार के लिए सभी विभागों के समन्वित प्रयास आवश्यक हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने कहा कि स्वस्थ माताएं और स्वस्थ बच्चे ही विकसित छत्तीसगढ़ की सबसे मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आदिम जाति विकास विभाग सहित सभी संबंधित विभाग यूनिसेफ के तकनीकी सहयोग से एक समन्वित और परिणामोन्मुख कार्ययोजना तैयार करें, जिससे शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुपोषण में कमी लाई जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजनाओं का प्रभाव तभी बढ़ेगा, जब विभिन्न विभाग साझा लक्ष्य और समन्वित कार्यप्रणाली के साथ काम करेंगे। उन्होंने अधिकारियों से ऐसी मल्टी-सेक्टोरल रणनीति तैयार करने को कहा, जिससे स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंचे और बच्चों के पोषण स्तर में गुणात्मक सुधार सुनिश्चित हो। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने सुश्री सिंथिया

मैककैफ्रे का शॉल एवं छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान के प्रतीक 'नंदी' भेंट कर आत्मीय स्वागत किया। वहीं सुश्री मैककैफ्रे ने भारत में यूनिसेफ के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी विशेष स्मारक डाक टिकट मुख्यमंत्री को भेंट किया। यूनिसेफ की भारत प्रतिनिधि सुश्री सिंथिया मैककैफ्रे ने मुख्यमंत्री का जय जोहार कहकर अभिवादन किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक सौंदर्य, समृद्ध संस्कृति और सरल-सहज लोगों का प्रदेश है। उन्होंने बताया कि यूनिसेफ लंबे समय से राज्य सरकार के साथ मिलकर मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण और बाल संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि राज्य सरकार और यूनिसेफ के संयुक्त प्रयासों से प्रदेश के बच्चों का भविष्य अधिक सुरक्षित, स्वस्थ और समृद्ध बनेगा। बैठक में मंत्रिमंडल के सदस्य, मुख्य सचिव श्री विकासशील, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव श्री सुबोध कुमार सिंह, छत्तीसगढ़ में यूनिसेफ की प्रमुख सुश्री सीमा कुमार, श्री अनिल गुलाटी तथा डॉ. बाल पारितोष दास उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री से लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने आगामी 18, 19 एवं 20 सितंबर को रायपुर में आयोजित होने वाले 14वें इंडिया इंडस्ट्रियल फेयर (आईआईएफ) की तैयारियों, उद्देश्यों एवं आयोजन की विस्तृत रूपरेखा से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री साय ने आयोजन की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे राष्ट्रीय स्तर के औद्योगिक आयोजन प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को नई दिशा देने के साथ-साथ निवेश, नवाचार और रोजगार सृजन को भी गति प्रदान करते हैं।

छत्तीसगढ़ में मानसून का असर तेज एक हफ्ते तक बारिश की संभावना

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ में मानसून का असर तेज, अगले 1 हफ्ते तक बारिश की संभावना, कई जिलों में अलर्ट जारी छत्तीसगढ़ में मानसून असर लगातार तेज होते जा रहा है. । प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में अगले एक सप्ताह तक बारिश होने की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। राजधानी रायपुर में मंगलवार सुबह-सुबह बूंदाबादी हुई. साथ ही आसमान में बादलों छाया हुआ है। अगले चौबीस घंटे में भी ज्यादा प्रभाव उत्तरी इलाका में रहने के आसार हैं। प्रदेश में गुरुवार से भारी बारिश का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ था, जिसका असर अगले एक दो दिन में समाप्त होने की संभावना बन रही है। पिछले चौबीस घंटे में मानसूनी गतिविधि उत्तरी इलाके में ही सिमटी रही और कुछ एक इलाकों में अतिभारी से भारी वर्षा हुई। रायपुर शहर और आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग ने 21 जुलाई को आकाश में बादल छाने रहने के अलावा बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। मौसम विशेषज्ञों मुताबिक 21 जुलाई को अधिकतर स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा या गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। भारी वर्षा का क्षेत्र एक दो स्थानों तक सीमित रह सकता है। कुछ दिन तक बारिश की गतिविधि में विराम लगा रहेगा, इसके बाद बंगाल की खाड़ी में नया सिस्टम तैयार होने की उम्मीद है, जो उत्तर-पश्चिम की ओर आगे बढ़ता है, तो प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। पिछले चौबीस घंटे में प्रतापपुर में 11, लवन, बलौदाबाजार में 7-7, मनोरा में 6, दर्गी, ओडगी, पलारी, माना में 5 सेमी. तक पानी बरसा है। मौसम विभाग ने कई जिलों में सुबह के समय बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है। गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, बलौदा बाज़ार, जांजगीर-चांपा, रायगढ़, बिलासपुर, कोरबा, दुर्ग, बेमेतरा और मुंगेली में 60 किमी की रफ्तार से हवाएं चलने, आकाशीय बिजली और बारिश की संभावना जताई गई है।

नगर निगम जोन 10 ने स्वच्छता व्यवस्था का किया औचक निरीक्षण

रायपुर। रायपुर नगर पालिक निगम जोन क्रमांक 10 स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छता से सम्बंधित प्राप्त जनशिकायत की वस्तुस्थिति की जानकारी लेने जोन 10 क्षेत्र अंतर्गत डुंडा बोरिया में स्थित देवी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट की स्वच्छता व्यवस्था का औचक निरीक्षण नगर निगम आयुक्त श्री संबित मिश्रा के निर्देश पर जोन 10 जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा के मार्गनिर्देशन में किया गया. स्वच्छता व्यवस्था के औचक निरीक्षण के दौरान गन्दगी फैलाया जाना और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम का उल्लंघन करना पाया गया. प्राप्त जनशिकायत स्थल पर पूरी तरह सही मिलने पर निर्देशानुसार जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा एवं स्वच्छता निरीक्षक यशवंत बेरिहा द्वारा देवी स्वीट्स डुठुस्र रेस्टोरेंट के सम्बंधित संचालक को भविष्य के लिए कड़ी चेतावनी।

कांग्रेस कार्यकाल की दूरदर्शिता से मिली थी 125 सीटों की सौगात

मेडिकल कॉलेज में अव्यवस्था का जिम्मेदार है भाजपा की सरकार......

रायपुर। संवाददाता

पूर्व संसदीय सचिव छग शासन एवं महासमुंद के पूर्व विधायक विनोद सेवन लाल चंद्राकर ने महासमुंद मेडिकल कॉलेज की बदहाल स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि कांग्रेस शासन में जनता की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से जिस दूरदर्शिता और संघर्ष के साथ महासमुंद में मेडिकल कॉलेज की स्थापना कराई गई थी, आज भाजपा की साय सरकार उसी विरासत को संभालने में पूरी तरह असफल साबित हो रही है। उन्होंने कहा कि उनके विधायकी कार्यकाल में कांग्रेस की भूपेश सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर प्रदेश के

दूरस्थ अंचल में चिकित्सा शिक्षा की अलख जगाई और कड़ी मेहनत के बाद महासमुंद मेडिकल कॉलेज को 125 एमबीएस सीटों की स्वीकृति दिलाई गई। यह स्वीकृति केवल एक घोषणा नहीं थी, बल्कि छत्तीसगढ़ के युवाओं को अपने ही प्रदेश में डॉक्टर बनने का अवसर देने और आम जनता को सस्ती व सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम था। श्री चंद्राकर ने कहा कि दुर्भाग्य की बात है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाजपा सरकार इस महत्वपूर्ण संस्थान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रही है। नेशनल मेडिकल कमीशन ने हाल ही में कॉलेज का निरीक्षण कर फैकल्टी, अस्पताल और हॉस्टल में गंभीर कमियां पाई हैं और सुधार के लिए मात्र 45 दिन का अल्टीमेटम दिया है। यह अल्टीमेटम कोई पहला नहीं है। हर साल इसी तरह की चेतावनी मिलती है, लेकिन भाजपा सरकार की लचर कार्यप्रणाली और काम करने की इच्छाशक्ति की कमी के कारण आज तक स्थिति नहीं सुधरी।

वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना बनी छत्तीसगढ़ कर्मचारियों का सहारा..

रायपुर। संवाददाता

छत्तीसगढ़ की प्रगति में एक ऐसा अध्याय जुड़ गया है, जो प्रशासनिक सुधार के साथ ही राज्य के लाखों शासकीय कर्मचारियों के जीवन में नई उम्मीद और सुरक्षा का संचार भी कर रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा प्रारंभ की गई 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना' सुशासन की दिशा में एक महवपूर्ण कदम है। कर्मचारी कल्याण को केंद्र में रखकर तैयार की गई यह योजना एक वित्तीय सुविधा, संवेदनशील शासन, आधुनिक तकनीक और मानवीय दृष्टिकोण का संगम है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट किया है कि शासकीय सेवक राज्य के विकास के मूल में हैं। राज्य के मुखिया का मानना है कि जब कर्मचारी मानसिक और आर्थिक रूप से सशक्त होंगे तभी वह शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक प्रभावी रूप से पहुंच पाएंगे। यही सोच इस योजना की आत्मा है। आज के दौर में स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक आवश्यकता या अन्य आपात स्थिति जैसी आकस्मिक परिस्थितियां किसी भी कर्मचारी को आर्थिक संकट में डाल सकती हैं। ऐसे विपरीत समय में उनको निजी साहूकारों या ऊँचे ब्याज दर वाले ऋण विकल्पों का सहारा लेना पड़ता है जिससे वे और अधिक मानसिक दबाव वाली परिस्थिति में आ जाते हैं। सीएम साय की 'वेतन के विरुद्ध अल्पावधि ऋण योजना' कर्मचारियों की आर्थिक समस्या का सीधा और सटीक समाधान प्रस्तुत करती है। बिना ब्याज, त्वरित और सम्मानजनक आर्थिक सहायता, डिजिटल क्रांति का सशक्त उदाहरण बन रहा है। ई-कोष प्रणाली की सबसे बड़ी शक्ति है इसका पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी स्वरूप का होना। ई-कोष (द्व-न्चश्चह्यद्ध) प्रणाली के माध्यम से इस योजना को लागू किया गया है इस सुविधा में कर्मचारी घर बैठे ही आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के तहत कर्मचारियों के द्वारा लिए गए ऋण पर कोई अतिरिक्त आर्थिक बोझ नहीं आता। आवेदन की पूरी प्रक्रिया पेपरलेस है जिसमें न फाइलों का झंझट है और न ही कार्यालय के चक्कर। इस योजना के लिए ई-केवाईसी आधारित सत्यापन एक तेज और सुरक्षित प्रक्रिया है। पारदर्शिता और समय की बचत के साथ भुगतान हितग्राहियों के बैंक खाते में सीधा पहुँचाया जा रहा है। प्राप्त ऋण का वेतन से आसानी से पुनर्भुगतान करने के लिए स्वचालित किस्त कटौती का प्रावधान है।

महादेव ऐप केस : ओमान में गिरफ्तार सौरभ चंद्राकर का फर्जी पासपोर्ट वायरल

रायपुर। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप के प्रमुख आरोपी सौरभ चंद्राकर की ओमान में गिरफ्तारी के बाद जांच में नया खुलासा सामने आया है। सोशल मीडिया पर उसका कथित फर्जी पासपोर्ट वायरल हो रहा है, जिसमें फोटो सौरभ चंद्राकर की है, लेकिन नाम श्रीलंकाई क्रिकेटर अजंता मेंडिस का दर्ज बताया जा रहा है। जांच एजेंसियों को आशंका है कि प्रत्यर्पण और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए उसने फर्जी पहचान का सहारा लिया। जांच एजेंसियों के अनुसार, सौरभ चंद्राकर ने कथित तौर पर फर्जी पासपोर्ट के जरिए ओमान में प्रवेश किया। पासपोर्ट संख्या श्व3387986 वाले दस्तावेज में उसे 11 मार्च 1998 को जन्मा दक्षिण-पूर्व एशियाई नागरिक दर्शाया गया है। दस्तावेज के अनुसार यह पासपोर्ट 21 जून 2024 को जारी हुआ था और इसकी वैधता 21 जून 2034 तक बताई गई है। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि यह फर्जी दस्तावेज किस नेटवर्क के माध्यम से तैयार किया गया और इसका उपयोग कैसे किया गया। जांच में यह भी सामने आया है कि सौरभ चंद्राकर और उसके सहयोगी रवि उप्पल ने पहले वानूआतू की नागरिकता हासिल की थी। उस दस्तावेज में सौरभ की जन्मतिथि 13 जनवरी 1995 दर्ज है, जबकि कथित फर्जी पासपोर्ट में जन्मतिथि 11 मार्च 1998 दिखाई गई है।

स्वस्थ पशुधन,समृद्ध किसान मुंगेली में 582 शिविरों से बदली पशुपालन की तस्वीर

- 07 लाख 67 हजार से अधिक पशुओं का हुआ टीकाकरण

रायपुर/ संवाददाता

मुंगेली जिले में पशुधन संरक्षण, उन्नत नस्ल विकास एवं पशुपालकों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पशुधन विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है। उपचार, टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, रोग नियंत्रण एवं गांव-गांव आयोजित स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से जिले में पशुपालन को नई दिशा मिली है। इन प्रयासों से पशुओं का स्वास्थ्य बेहतर होने के साथ दुग्ध उत्पादन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है। उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. आर.एम. त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान जिले में 67 हजार 257 पशुओं का उपचार किया गया। वहीं एक लाख 22 हजार 804 पशुओं को औषधियों का वितरण, 93 हजार 561 पशुओं को कृमिनाशक दवा तथा एक लाख 09 हजार 84 पशुओं को किलनी मुक्त करने के लिए डिटिकिंग की गई। पशु स्वास्थ्य सेवाओं के इस व्यापक अभियान से हजारों पशुपालकों को सीधा लाभ मिला। नस्ल सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 09 हजार 978 निकृष्ट सांडों का बंधियाकरण किया गया। साथ ही 20 हजार 341 गाय एवं भैंसों में कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, जिसके परिणामस्वरूप 05 हजार 685 उन्नत नस्ल के बछड़ों का जन्म हुआ। इनमें 02 हजार 900 से अधिक मादा बछियां शामिल हैं, जो भविष्य में अधिक दुग्ध उत्पादन कर पशुपालकों की आय में महत्वपूर्ण वृद्धि करेंगी। छत्तीसगढ़ शासन की लिंग वर्गीकृत वीर्य योजना के तहत 123 गायों का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया, जिससे 99 मादा बछियों का जन्म हुआ। यह उपलब्धि जिले में उच्च उत्पादक पशुधन तैयार करने की दिशा में एक बड़ी सफलता है। पशुओं को संक्रामक एवं जानलेवा बीमारियों से सुरक्षित रखने के लिए जिले के 02 लाख 59 हजार 348 पशुधन में 07 लाख 67 हजार 531 प्रतिबंधात्मक टीकाकरण किए गए। इनमें गलघोंटू एवं एकटंगिया, खुरहा-चपका, लम्पी स्किन डिजीज, इंटरोटॉक्सीमिया तथा पीपीआर जैसी बीमारियों से बचाव के टीके शामिल हैं। इसके अतिरिक्त ब्रूसेलोसिस की रोकथाम के लिए 881 बछियों का टीकाकरण तथा 04 हजार 63 पशुओं को एंटी रेबीज वैक्सीन लगाई गई। पशु रोगों की समय पर पहचान के लिए रक्त, गोबर, ट्यूबरक्लोसिस एवं जॉन्सडिसीज सहित विभिन्न प्रयोगशाला जांच भी नियमित रूप से की गईं। पशुपालकों को घर के समीप बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिले में 582 बहुउद्देशीय पशु स्वास्थ्य एवं टीकाकरण शिविरों का आयोजन किया गया।

बालोद में असर दिखा रही प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना

गुरूर के आशुतोष पंचागम का बिजली बिल 10 हजार रुपए से घटकर हुआ 12 सौ रुपए

- सौर ऊर्जा से बढ़ी बचत और आत्मनिर्भरता, 3 किलोवाट के सोलर प्लांट पर 1.08 लाख रुपए की मिली सहायता

रायपुर/ संवाददाता

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की महत्वाकांक्षी प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना और मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में इसके प्रभावी क्रियान्वयन से छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिल रही है। बालोद जिले में भी यह योजना आम नागरिकों के जीवन में सकारात्मक

बदलाव ला रही है। जिले के गुरूर निवासी श्री आशुतोष पंचागम इसका प्रेरणादायी उदाहरण हैं, जिन्होंने अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का रूफटॉप सोलर प्लांट स्थापित कर बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी हासिल की है। पिछले सात महीनों से संचालित इस सोलर प्लांट का लाभ अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। आशुतोष पंचागम बताते हैं कि सोलर प्लांट लगने से शुरुआती महीनों में उनका बिजली बिल पूरी तरह शून्य रहा। वहीं भीषण गर्मी के मौसम में, जब घर में एयर कंडीशनर, कूलर और पंखों का अधिक उपयोग हुआ, तब भी उनका बिजली बिल, जो पहले 8 से 10 हजार रुपये तक पहुंच जाता था, घटकर लगभग 1200 से 1500 रुपये रह गया। आशुतोष पंचागम ने बताया कि योजना के तहत आवेदन की पूरी प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और नागरिकों के लिए सुविधाजनक है। आवेदन के बाद अधिकृत वेंडर द्वारा घर का निरीक्षण किया गया तथा ऋण और सब्सिडी से संबंधित सभी जानकारियां उपलब्ध कराई गईं। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद कम समय में ही उनके घर पर सोलर प्लांट स्थापित कर दिया गया। उन्होंने बताया कि इस योजना के अंतर्गत उन्हें केंद्र एवं राज्य सरकार से कुल 1 लाख 8 हजार रुपए की सब्सिडी प्राप्त हुई, जिससे सोलर प्लांट लगाने का आर्थिक बोझ काफी कम हो गया।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय दुर्ग में ई-कोर्ट परियोजना के नवीन डिजिटल मॉड्यूलों पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

दुर्ग। ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत न्यायालयों में डिजिटल तकनीकों के प्रभावी क्रियान्वयन तथा न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित, सुगम एवं तकनीक-सक्षम बनाने के उद्देश्य से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय, दुर्ग के चतुर्थ तल स्थित नवीन सभागार में न्याय श्रुति, ई-साक्ष्य, ई-समन, ई-चालान, सीसीटीएनएस तथा आईसीजेएस विषयों पर एक दिवसीय कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। कार्यशाला का संचालन एवं समन्वय दीपक कोशले, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग तथा रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), दुर्ग द्वारा किया गया। कार्यक्रम में जिला न्यायपालिका के समस्त न्यायिक अधिकारियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यशाला में ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित नवीन डिजिटल मॉड्यूलों के व्यावहारिक उपयोग, उनकी कार्यप्रणाली तथा न्यायालयीन कार्यों में उनके प्रभावी क्रियान्वयन का विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस दौरान न्याय श्रुति के माध्यम से न्यायालयीन कार्यवाही के डिजिटल ट्रांसक्रिप्शन, ई-साक्ष्य द्वारा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के सुरक्षित एवं सुव्यवस्थित प्रबंधन, ई-समन के माध्यम से समन की त्वरित एवं पारदर्शी तामील, ई-चालान प्रणाली के प्रभावी उपयोग, सीसीटीएनएस के माध्यम से पुलिस एवं न्यायालय के मध्य सूचना समन्वय तथा आईसीजेएस के माध्यम से न्यायालय, पुलिस, जेल एवं अन्य अन्वेषण एजेंसियों के बीच डिजिटल सूचना के निर्बाध आदान-प्रदान की प्रक्रिया का व्यवहारिक प्रदर्शन किया गया। कार्यशाला के दौरान माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप सभी न्यायिक अधिकारियों को इन डिजिटल प्रणालियों के अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया। साथ ही प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए विभिन्न मॉड्यूलों के व्यवहारिक एवं तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग के. विनोद कुजूर ने अपने उद्बोधन में कहा कि - ई-कोर्ट परियोजना भारतीय न्यायपालिका को आधुनिक, पारदर्शी एवं नागरिक-केंद्रित न्याय व्यवस्था की ओर अग्रसर करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। सूचना प्रौद्योगिकी का प्रभावी उपयोग न केवल न्यायिक कार्यों की गति एवं गुणवत्ता में वृद्धि करेगा, बल्कि न्यायालयों की कार्यप्रणाली को अधिक उत्तरदायी, दक्ष एवं पारदर्शी भी बनाएगा। न्यायिक अधिकारियों द्वारा इन डिजिटल मॉड्यूलों का समुचित एवं नियमित उपयोग न्याय वितरण प्रणाली को नई दिशा प्रदान करेगा तथा आम नागरिकों को समयबद्ध एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के संवैधानिक उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए दीपक कोशले, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, दुर्ग ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित न्यायिक व्यवस्था न्याय वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं उत्तरदायी बनाएगी तथा नागरिकों को शीघ्र एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के उद्देश्य को और अधिक सशक्त करेगी। रवि महोबिया, व्यवहार न्यायाधीश (वरिष्ठ श्रेणी), दुर्ग ने सभी न्यायिक अधिकारियों से आग्रह किया कि वे ई-कोर्ट परियोजना के अंतर्गत विकसित सभी डिजिटल मॉड्यूलों का नियमित, प्रभावी एवं उत्तरदायित्वपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करें, जिससे न्यायालयों में डिजिटल कार्यसंस्कृति को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। कार्यशाला का समापन सभी न्यायिक अधिकारियों द्वारा ई-कोर्ट परियोजना के विभिन्न डिजिटल मॉड्यूलों के प्रभावी क्रियान्वयन, न्यायालयों में तकनीक आधारित कार्यप्रणाली को सुदृढ़ करने तथा आम नागरिकों को अधिक पारदर्शी, त्वरित एवं सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के सामूहिक संकल्प के साथ हुआ।

भिलाई निगम का वर्षाजल संरक्षण से भू-जल स्तर बढ़ाने पर जोर

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा शहर में भू-जल स्तर को संरक्षित एवं बढ़ाने के उद्देश्य से रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लेकर लगातार जागरूकता एवं प्रोत्साहन अभियान चलाया जा रहा है। निगम द्वारा भवन एवं भूमि मालिकों से अपने परिसरों में वर्षाजल संरक्षण के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम अनिवार्य रूप से स्थापित करने की अपील की जा रही है, ताकि आने वाले समय में जल संकट से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके। निगम अधिकारियों ने बताया कि लगातार गिरते भू-जल स्तर को संतुलित बनाए रखने के लिए वर्षा जल का संचयन सबसे प्रभावी और वैज्ञानिक उपाय है। वर्षा के पानी को सीधे जमीन में पहुंचाकर जलभृत को पुनर्भरित किया जा सकता है, जिससे भू-जल की उपलब्धता में वृद्धि होती है और प्राकृतिक जल स्रोत लंबे समय तक सुरक्षित बने रहते हैं। नगर निगम के अनुसार रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को सरकारी भवनों, निजी संस्थानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सामाजिक संस्थाओं तथा आवासीय परिसरों में आसानी से स्थापित किया जा सकता है। यह प्रणाली अपेक्षाकृत कम लागत वाली, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल तकनीक है, जो भविष्य की जल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। विशेषज्ञों के अनुसार वर्षा जल स्वाभाविक रूप से अपेक्षाकृत स्वच्छ एवं बैक्टीरिया रहित होता है, इसलिए इसके उपयोग के लिए अत्यधिक जल शुद्धिकरण की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसके माध्यम से भू-जल का पुनर्भरण होने से सूखे की स्थिति का प्रभाव कम होता है, नदियों और अन्य प्राकृतिक जल स्रोतों के प्रवाह को बनाए रखने में सहायता मिलती है तथा जल प्रदूषण की समस्या में भी कमी आती है। निगम ने बताया कि सतही जल की तुलना में भू-जल स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक सुरक्षित माना जाता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के माध्यम से जल का वाष्पीकरण भी कम होता है, जिससे जल का संरक्षण बेहतर तरीके से हो पाता है और जलभृत की उत्पादक क्षमता में भी वृद्धि होती है। नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से अपील की है कि वे वर्षा ऋतु का अधिकतम लाभ उठाते हुए अपने घरों, भवनों और संस्थानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करें। नागरिकों की सक्रिय भागीदारी से ही जल संरक्षण का यह अभियान सफल होगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त भू-जल संसाधन सुरक्षित रखे जा सकेंगे।

भिलाई निगम ने सेक्टर-6 ए मार्केट की दुकानों का किया सर्वे, संपत्तिकर निर्धारण के लिए माप कार्य शुरू

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई की आयुक्त सुश्री सुरूचि सिंह के निर्देशानुसार निगम क्षेत्र में संपत्तिकर निर्धारण एवं आरोपण की प्रक्रिया को गति देते हुए बीएसपी क्षेत्र में निर्मित भवनों एवं भूमियों का परिमाप (माप) और सर्वे कार्य लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को सेक्टर-6 ए मार्केट स्थित दुकानों का विस्तृत माप एवं सर्वे किया गया। निगम द्वारा संचालित इस अभियान का उद्देश्य बीएसपी क्षेत्र में स्थित व्यावसायिक एवं अन्य परिसरों का वास्तविक क्षेत्रफल दर्ज कर संपत्तिकर का वैज्ञानिक एवं पारदर्शी निर्धारण करना है। सर्वे के दौरान दुकानों के आयाम, निर्मित क्षेत्र एवं अन्य आवश्यक जानकारियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया, जिससे भविष्य में कर निर्धारण की प्रक्रिया अधिक सटीक और व्यवस्थित हो सके। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि संपत्तिकर सर्वे अभियान चरणबद्ध तरीके से पूरे निगम क्षेत्र में संचालित किया जा रहा है। इससे कर व्यवस्था में पारदर्शिता आएगी, राजस्व संग्रह में वृद्धि होगी तथा निगम को शहर के विकास कार्यों के लिए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध होंगे। साथ ही सभी संपत्तियों का अद्यतन रिकॉर्ड तैयार होने से कर संबंधी विसंगतियों को भी दूर किया जा सकेगा। इस दौरान निगम की सर्वे टीम ने दुकानदारों से सहयोग की अपील करते हुए आवश्यक दस्तावेज एवं जानकारी उपलब्ध कराने का आग्रह किया। अधिकांश व्यापारियों ने सर्वे कार्य में सहयोग प्रदान किया।

सर्वे अभियान के दौरान सहायक राजस्व अधिकारी अनिल मेश्राम, सहायक राजस्व निरीक्षक प्रहलाद लहरे, गणित बद्येल, प्रकाश महिलवार एवं महेन्द्र बाघमारे सहित निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि आने वाले दिनों में बीएसपी क्षेत्र के अन्य सेक्टरों एवं बाजारों में भी संपत्तिकर निर्धारण के लिए इसी प्रकार का सर्वे एवं माप कार्य जारी रहेगा।

शिक्षा विभाग के जेडी, डीईओ एवं बीईओ कार्यालयों के स्थान पर आधुनिक कॉम्पोजिट कार्यालय भवन का होगा निर्माण

शिक्षा एवं खेल अधोसंरचना के लिए की चार महत्वपूर्ण घोषणाएं

दुर्ग शहर में सर्वसुविधायुक्त ऑडिटोरियम, खेल प्रतिभाओं के लिए फुटबॉल मैदान सह एथलेटिक्स ट्रैक तथा नीट एवं जेईई की तैयारी करने वाले छात्र-छात्राओं के लिए 100-100 सीटर छात्र एवं छात्रा छात्रावास की स्थापना की हुई घोषणा

दुर्ग। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन आज दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जामगांव (एम) में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय थे। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री गजेन्द्र यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक श्री ललित चन्द्राकर, साजा विधायक श्री ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष श्री राकेश पाण्डेय, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष श्री जितेन्द्र साहू, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, दुर्ग संभाग आयुक्त श्री सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक श्री अभिषेक शांडिल्य, आयुक्त समग्र शिक्षा श्रीमती किरण कौशल तथा कलेक्टर श्री अभिजीत सिंह भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। नवप्रवेशी बच्चों का आत्मीय स्वागत, अध्ययन सामग्री एवं सायकल का वितरण-मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय एवं अतिथियों ने विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कक्षा पहली, छठवीं एवं नवमी के चयनित विद्यार्थियों को पुस्तकों एवं गणवेश का वितरण किया तथा कक्षा नवमी की पात्र छात्राओं को सायकल प्रदान की। कक्षा पहली के नवप्रवेशी विद्यार्थियों में भूपेन्द्र सिंह पहाड़ी, पार्थ यादव, वीर चंद्राकर, विवान ठाकुर, यश मारकंडे, डाली सिन्हा, दिव्यांशी, लावन्या साहू, लिशिका चंद्राकर एवं मानवी सेन शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें और अपने ज्ञान, प्रतिभा एवं संस्कारों से समाज और प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है और राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और जीवन में सफलता का सबसे सशक्त आधार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, समय पर पुस्तक एवं गणवेश वितरण, अतिरिक्त पौष्टिक आहार, नियमित पालक-शिक्षक बैठक, न्योता भोज जैसी अनेक अभिनव पहलें संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री श्री से ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं तथा 24 नालंदा परिसर विकसित किए जा चुके हैं। दिल्ली में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 200 सीट क्षमता वाले छात्रावास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में कोई भी विद्यालय शिक्षकविहीन नहीं है तथा बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा के नए केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। जगरगुंडा में एजुकेशन हब विकसित किया जा रहा है।

समय रहते नहीं की सड़क की नविनिकरण, बारिश में विकराल हुआ समस्या

क्या किसी की बली लेकर मानेगा जिला प्रशासन

बलौदा बाजार । बलौदा बाजार से सिमगा मार्ग इन दोनों अत्यधिक जर्जर स्थिति में पहुंच गया है समय रहते मार्ग का नवीनीकरण नहीं किया गया जिसका हर्जाना अब ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बलौदा बाजार से शिमला मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं इन गधों के चलते ग्रामीणों को अत्यधिक परेशानी हो रही है रोजी- मजदूरी करने वाले ग्रामीणों व स्कूल आने जाने वाले छात्र-छात्राओं सहित आम नागरिक काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं।अंतरराष्ट्रीय स्तर के सीमेंट संयंत्रों के कच्चा माल एवं पक्का माल ढोने वाले भारी का वाहनों ने सड़क की ऐसी दुर्दशा कर दी की पैदल चलना भी कठिन हो हो गया है मार्ग में शाम होते ही ओवरलोडिंग का खेल शुरू हो जाता है जो वर्षों से निरंतर जारी है। मार्ग ओवरलोडिंग वाहनों पर कार्रवाई नहीं होने इसके चलते सड़क की स्थिति अत्यधिक जर्जर होते जा रही है। सुहेला, नवापारा, हथबंद पड़कीडीह , करही चांडी, सेमहराडीह, रिसदा, कोकड़ी सहित इत्यादि गांवों के ग्रामीणों ने तत्काल गड्ढों को भरने मांग किया है।

राष्ट्रीय रथयात्रा सेवा शिविर में शामिल हुए दुर्ग के रीतेश कुमार ताम्रकार ...

दुर्ग। भारत स्काउट्स एवं गाइड्स, छत्तीसगढ़ के राज्य मुख्य आयुक्त श्री इंदरजीत सिंह खालसा एवं राज्य सचिव श्री बृजेश कुमार बाजपेयी के निर्देशन तथा जिला अध्यक्ष अशोक देशमुख, जिला मुख्य आयुक्त जीत यादव और जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला कमिश्नर अरविंद मिश्रा के मार्गदर्शन में दुर्ग जिले के रीतेश कुमार ताम्रकार (एडवांस रोवर), सुभाष ओपन रोवर वरू, (स्टाफ) में किया गया है।

राष्ट्रीय मुख्यालय, नई दिल्ली द्वारा आयोजित यह राष्ट्रीय रथयात्रा सेवा शिविर 14 से 18 जुलाई 2026 तक विश्वविद्यालय परिसर, पुरी (ओडिशा) में आयोजित किया गया। इस प्रतिष्ठित शिविर में संचालन दल के सदस्य के रूप में चयन होना जिले के लिए गौरव की बात मानी जा रही है।

रीतेश कुमार ताम्रकार के राष्ट्रीय दुर्ग का चयन राष्ट्रीय स्तर के रथयात्रा सेवा शिविर के संचालन दल स्तर पर चयन से स्काउट-गाइड परिवार एवं शुभचिंतकों में हर्ष का माहौल है। सभी ने उनके उत्कृष्ट सेवा कार्यों की सराहना करते हुए इसे दुर्ग जिला एवं छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सम्मानजनक उपलब्धि बताया।

जिला संगठन आयुक्त (बालक) दास राऊत ने रीतेश कुमार ताम्रकार को इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की तथा विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट सेवाएं देकर जिले और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

सीएम पोर्टल की शिकायत पर निगम ने की कार्रवाई, खुले में संचालित मांस-मटन दुकान पर चला अभियान

भिलाईनगर। नागरिकों की शिकायतों के त्वरित निराकरण एवं शहर में स्वच्छता व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से निगम द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में सीएम पोर्टल पर प्राप्त शिकायत के आधार पर निगम के जोन-3 राजस्व विभाग एवं बेदखली शाखा की संयुक्त टीम ने 18 नंबर रोड, कैम्प-01 क्षेत्र में खुले में संचालित मांस-मटन दुकान के विरुद्ध कार्रवाई की। निरीक्षण के दौरान टीम ने पाया कि संबंधित दुकान खुले में मांस-मटन का विक्रय कर रही थी, जिससे आसपास के क्षेत्र में गंदगी फैलने के साथ-साथ आम नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। खुले में मांस विक्रय किए जाने से स्वच्छता एवं स्वास्थ्य संबंधी नियमों का भी उल्लंघन हो रहा था। शिकायत की गंभीरता को देखते हुए निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्रवाई करते हुए संबंधित संचालक को नियमों का पालन करने के निर्देश दिए। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक स्थानों पर खुले में मांस-मटन का विक्रय करना न केवल स्वच्छता व्यवस्था को प्रभावित करता है, बल्कि इससे संक्रमण एवं दुर्गंध जैसी समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसे मामलों में निगम द्वारा नियमानुसार कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि सीएम पोर्टल सहित विभिन्न माध्यमों से प्राप्त नागरिक शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि शहर में स्वच्छ, व्यवस्थित एवं स्वस्थ वातावरण बनाए रखना नगर निगम की सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा नियमों का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के विरुद्ध बिना किसी भेदभाव के कठोर कार्रवाई की जाएगी।

नगर पालिक निगम भिलाई ने शहरवासियों से भी अपील की है कि वे स्वच्छता नियमों का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की अव्यवस्था, अतिक्रमण अथवा सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े मामलों की जानकारी सीएम पोर्टल अथवा निगम के संबंधित जोन कार्यालय में दें।

स्वास्थ्य कर्मियों की वेतन विसंगति और ऑनलाइन एंट्री सहित कई मांगों पर शासन का ध्यान आकृष्ट

छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने स्वास्थ्य मंत्री और स्वास्थ्य विभाग के सचिव भेजा पत्र

भिलाई। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और स्वास्थ्य विभाग के सचिव अमित कटारिया से प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारियों की मूलभूत मांगों की ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र निराकरण की मांग की है। उन्होंने अपने पत्र में कहा है कि लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कैडरों की मांगे शासन स्तर और संचालनालय स्तरों पर लंबित है। इनमें वेतन विसंगति, एक समय पर ओ पी डी संचालन, विभिन्न कैडरों की पदोन्नति , जीवन दीप समिति कर्मचारियों का नियमितीकरण और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर निर्णय लिया जाना चाहिए। सैय्यद असलम ने कहा फील्ड का कर्मचारी स्वास्थ्य सेवाओं को ऑनलाइन एंट्री करने 20 पोर्टल मे दर्ज कर रहा है। उसके साथ इनकी जानकारी ऑफ लाइन भी रखता है क्योंकि अधिकांश पोर्टल सुरक्षित नहीं है। कई-कई घंटों मे दी गई स्वास्थ्य सेवाओं का विवरण पोर्टल मे दर्ज होता है। इन सब जानकारी के लिए स्वास्थ्य महकमा फील्ड स्वास्थ्य कर्मचारी कब जाएं, यह बड़ी चुनौती है। उसे हितग्राहियों का सेवा विस्तार स्वास्थ्य का विवरण पोर्टल मे दर्ज करने वास्तविक जांच करनी होगी। वहीं इसका लक्ष्य प्राप्त करने फील्ड मे कब जाएं और कब मरीजों को सेवा दे, इस पर कठिनाई हो रही है। उन्होंने कहा कि इन दिक्कतों के बीच स्वास्थ्य कर्मचारी मानसिक रूप से बीमार हो रहा है। नोडल अधिकारियों का प्रतिदिन वीडियो कांफ्रेंसिंग (वी सी) लेने का अलग रिवाज बन गया है। नोडल अफसर खुद फील्ड में जाते नहीं है लेकिन वीसी मे कर्मचारियों को फ़रमान पे फ़रमान देकर दो दिन तीन मे लक्ष्य पूरा करने दबाव बनाते हैं। इम्पेक्स के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ओ पी शर्मा ने इस संबंध मे कहा कि स्वास्थ्य विभाग मे रिक्त पदों को भरना पड़ेगा ओर स्वास्थ्य विभाग के नियमित पदों को जीवंत रखना होगा। निजीकरण से स्वास्थ्य सेवाएं सुदृढ ना होकर बेहाल ओर बेलगाम हो जाएगी। प्रदेश महामंत्री सैय्यद असलम ने स्वास्थ्य विभाग का विभिन्न कार्यक्रमों के अलग अलग रिपोर्टिंग पोर्टल को एक पोर्टल बनाने का सुझाव देते हुए ओ टी पी की अनिवार्यता समाप्त करने एवं डाटा एंट्री ऑपरेटर प्रत्येक एच डब्लू सी और स्वास्थ्य केंद्र में नियुक्त करने की मांग रखी है।

प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत बीएसपी में 40 प्रशिक्षुओं का ओरिएंटेशन एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न

भिलाई। सेल-भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के मानव संसाधन ज्ञानार्जन एवं विकास (एचआर-एल एंड डी) विभाग द्वारा प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) के अंतर्गत चयनित 40 प्रशिक्षुओं के लिए ओरिएंटेशन एवं औद्योगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन जुलाई माह में किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रशिक्षुओं को औद्योगिक कार्यप्रणाली, संगठनात्मक संस्कृति तथा इस्पात उद्योग की उत्पादन प्रक्रियाओं से व्यावहारिक रूप से परिचित कराना था। प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ दो दिवसीय ओरिएंटेशन सत्र के साथ हुआ, जिसमें प्रशिक्षुओं को भिलाई इस्पात संयंत्र की कार्यप्रणाली, एकीकृत इस्पात संयंत्र की उत्पादन प्रक्रिया, औद्योगिक सुरक्षा, कार्यस्थल अनुशासन तथा संगठनात्मक कार्य संस्कृति की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई। इसके पश्चात दो दिवसीय संयंत्र भ्रमण का आयोजन किया गया, जिसके दौरान प्रशिक्षुओं ने संयंत्र की प्रमुख उत्पादन इकाइयों का अवलोकन कर विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं एवं आधुनिक उत्पादन प्रणालियों का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त किया। उल्लेखनीय है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना (पीएमआईएस) का उद्देश्य युवाओं को शैक्षणिक शिक्षा के साथ उद्योगों में व्यावहारिक अनुभव प्रदान कर शिक्षा एवं उद्योग के मध्य की दूरी को कम करना, उनकी रोजगार क्षमता का विकास करना तथा उन्हें भविष्य की औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप दक्ष बनाना है। यह योजना कुशल एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यह कार्यक्रम महाप्रबंधक प्रभारी (मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास) संजीव कुमार श्रीवास्तव के मार्गदर्शन में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के समन्वय में उप प्रबंधक (मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास) सुष्मिता पाटला, सेक्शन अधिकारी (मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास) स्वतंत्र कुमार तथा टेक्निकल एसोसिएट (मानव संसाधन-ज्ञानार्जन एवं विकास) मनीष कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

रमन सिंह बोले...स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मनिर्भरता की चाबी

विधानसभा अध्यक्ष ने 150 हितग्राहियों को वितरित किए प्रॉपर्टी कार्ड

प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का अधिकाधिक लाभ लेने की अपील

राजनांदगांव। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह स्पीकर निवास में आयोजित स्वामित्व योजना अंतर्गत स्वामित्व पट्टा वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने राजनांदगांव विकासखंड के ग्राम ईरा, मनकी, आरला, बांकल एवं कुसमी के 150 हितग्राहियों को स्वामित्व पट्टों का वितरण किया। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उपलब्ध कराई गई एम्बुलेंस एवं स्वच्छता वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना भी किया। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड केवल कागज का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि ग्रामीणों के आत्मसम्मान, आत्मनिर्भरता की चाबी है। उनके कानूनी अधिकार का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि वर्षों से ग्रामीण आबादी की भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 24 अप्रैल 2020 को प्रारंभ की गई स्वामित्व योजना के माध्यम से अब प्रत्येक ग्रामीण परिवार को उसकी आवासीय भूमि का प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अत्याधुनिक ड्रोन सर्वे एवं डिजिटल मैपिंग के माध्यम से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण किया गया है। अब प्रत्येक मकान एवं भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों को उनकी संपत्ति का विधिवत स्वामित्व प्राप्त होगा। कलेक्टर ने बताया कि राजनांदगांव जिले के 654 ग्रामों में प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जाने हैं। इनमें से 186 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। पूर्व में 24 ग्रामों के 1 हजार 283 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। आज 5 ग्रामों के 150 हितग्राहियों को प्रॉपर्टी कार्ड प्रदान किए गए। कलेक्टर ने कहा कि स्वामित्व योजना से ग्रामीणों को उनकी संपत्ति पर कानूनी अधिकार मिलेगा, बैंक से ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी, भूमि संबंधी विवादों में कमी आएगी।

सर्वे और अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूरी

उन्होंने बताया कि जिले के अनेक गांवों में सर्वे एवं अंतिम प्रकाशन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है तथा चरणबद्ध तरीके से सभी गांवों में शिविर लगाकर स्वामित्व कार्ड वितरित किए जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सिंह ने कहा कि स्वामित्व कार्ड मिलने से ग्रामीण अपनी संपत्ति का विधिक प्रमाण प्राप्त करेंगे। इसके आधार पर बैंकों से ऋण प्राप्त करना भी आसान होगा, जिससे ग्रामीण आर्थिक रूप से सशक्त एवं आत्मनिर्भर बन सकेंगे। उन्होंने कहा कि यह योजना गांवों के विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

सौर पैनल लगाने विस अध्यक्ष ने कही बात

उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना का उल्लेख करते हुए ग्रामीणों से अधिक से अधिक संख्या में अपने घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सोलर संयंत्र स्थापना पर आकर्षक अनुदान दिया जा रहा है। इससे बिजली का बिल शून्य होने के साथ अतिरिक्त बिजली उत्पादन से आय अर्जित करने का अवसर भी मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिन हितग्राहियों को स्वामित्व कार्ड प्राप्त हुआ है, वे बैंक से ऋण लेकर भी सोलर संयंत्र स्थापित कर सकते हैं और योजना का अधिकतम लाभ उठा सकते हैं।

गभरा का आंवला बगीचा बना मुरूम भंडारण केंद्र, कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों में नाराजगी सरपंच के बातों का भी अवहेलना

पाटन। पाटन विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत करगा-गभरा में स्थित शासकीय आंवला बगीचा इन दिनों कथित रूप से मुरूम भंडारण का केंद्र बन गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि मुरूम कारोबारी खुलेआम बगीचे में पेड़-पौधों के नीचे बड़ी मात्रा में मुरूम का भंडारण कर रहे हैं, जबकि इस पर रोक लगाने के बावजूद अब तक कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई है। जानकारी के अनुसार, ग्राम पंचायत के सरपंच कमलेश ठाकुर ने आंवला बगीचा में मुरूम भंडारण करने से मना किया था और भंडारित मुरूम हटाने की बात भी कही गई थी। इसके बावजूद आज तक मुरूम नहीं हटाया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि आंवला बगीचा बस्ती के समीप स्थित है, जहां तीज-त्योहार के अवसर पर महिलाएं और बच्चे घूमने आते हैं तथा बच्चे खेलकूद करते हैं। ऐसे सार्वजनिक स्थान पर बड़ी मात्रा में मुरूम का भंडारण होने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सूत्रों के अनुसार, मुरूम कारोबारी द्वारा सैकड़ों हाइवा मुरूम का भंडारण किया गया है, जिसे मांग के अनुसार ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। बारिश के मौसम में मुरूम की मांग बढ़ने के कारण शासकीय भूमि पर अवैध भंडारण किए जाने की शिकायतें सामने आती रही हैं, लेकिन गभरा में आंवला बगीचा तक को भंडारण स्थल बना दिए जाने से ग्रामीणों में नाराजगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि संबंधित विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे कार्रवाई को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।

राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव में कुम्हारी व जंजगीरी के मेधावी विद्यार्थियों का मुख्यमंत्री ने किया सम्मान

पाटन। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जामगांव एम में आयोजित राज्य स्तरीय शाला प्रवेश उत्सव के दौरान नगर पालिका परिषद कुम्हारी क्षेत्र के पीएम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय, कुम्हारी तथा सेजेस जंजगीरी के मेधावी विद्यार्थियों को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने सम्मानित किया। कायक्रम में राष्ट्रीय साधन सह प्राविण्य छात्रवृत्ति (एनएमएमएस) परीक्षा वर्ष 2025-26 में राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर पायल रजनी (पीएमश्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय, कुम्हारी) को राज्य में प्रथम स्थान, नैतिक आमटे (पीएमश्री स्वामी आत्मानंद विद्यालय, कुम्हारी) को राज्य में सातवां स्थान तथा श्रद्धा इंदौरिया (सेजेस, जंजगीरी) को राज्य में दसवां स्थान प्राप्त करने पर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय एवं उपस्थित अतिथियों ने सम्मानित किया। मुख्यमंत्री ने सभी मेधावी विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं तथा कहा कि ऐसे विद्यार्थी प्रदेश के अन्य छात्रों के लिए प्रेरणा हैं। सम्मान समारोह के दौरान जनप्रतिनिधियों, शिक्षा विभाग के अधिकारियों, शिक्षकों एवं बड़ी संख्या में उपस्थित विद्यार्थियों ने मेधावी छात्र-छात्राओं की उपलब्धि पर हर्ष व्यक्त किया। मौके पर शिक्षक एम एल साहू, शीतल नायर, दीप्ति पिलई, सुजिता, खिलेश वर्मा, नरोत्तम साहू उपस्थित रहे।

शिक्षा ही विकसित छत्तीसगढ़ का आधार : मुख्यमंत्री

शिक्षा एवं खेल अधोसंरचना के लिए की चार महत्वपूर्ण घोषणाएं

दुर्ग। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 के अंतर्गत राज्य स्तरीय शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन दुर्ग जिले के पाटन विकासखंड स्थित स्वामी आत्मानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय, जामगांव (एम) में उत्साह एवं गरिमामय वातावरण में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय थे। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चन्द्राकर, साजा विधायक ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पाण्डेय, तेलघानी विकास बोर्ड के अध्यक्ष जितेन्द्र साहू, स्कूल शिक्षा सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, दुर्ग संभाग आयुक्त सत्यनारायण राठौर, पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य, आयुक्त समग्र शिक्षा मती किरण कौशल तथा कलेक्टर अभिजीत सिंह भी उपस्थित रहे। बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सहभागिता की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एवं अतिथियों ने विद्यालय में पहली बार प्रवेश लेने वाले बच्चों का तिलक लगाकर एवं मुंह मीठा कराकर आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कक्षा पहली, छठवीं एवं नवमी के चयनित विद्यार्थियों को पुस्तकों एवं गणवेश का वितरण किया तथा कक्षा नवमी की पात्र छात्राओं को सायकल प्रदान की। कक्षा पहली के नवप्रवेशी विद्यार्थियों में भूपेन्द्र सिंह पहाड़ी, पार्थ यादव, वीर चंद्राकर, विवान ठाकुर, यश मारकंडे, डाली सिन्हा, दिव्यांशी, लावन्या साहू, लिशिका चंद्राकर एवं मानवी सेन शामिल रहे। मुख्यमंत्री ने सभी बच्चों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे मन लगाकर अध्ययन करें और अपने ज्ञान, प्रतिभा एवं संस्कारों से समाज और प्रदेश का नाम रोशन करें। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि शिक्षा ही विकास का मूल मंत्र है और राज्य सरकार प्रत्येक बच्चे तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल सरकारी नौकरी प्राप्त करने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज सेवा, राष्ट्र निर्माण और जीवन में सफलता का सबसे सशक्त आधार है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में स्मार्ट क्लास, समय पर पुस्तक एवं गणवेश वितरण, अतिरिक्त पौष्टिक आहार, नियमित पालक-शिक्षक बैठक, न्योता भोज जैसी अनेक अभिनव पहले संचालित की जा रही हैं। मुख्यमंत्री से ने कहा कि राज्य में वर्तमान में 15 मेडिकल कॉलेज संचालित हैं तथा 24 नालंदा परिसर विकसित किए जा चुके हैं। दिल्ली में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए 200 सीट क्षमता वाले छात्रावास की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि युक्तियुक्तकरण के बाद प्रदेश में कोई भी विद्यालय शिक्षक विहीन नहीं है तथा बस्तर सहित दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा के नए केन्द्र विकसित किए जा रहे हैं। जगरगुंडा में एजुकेशन हब विकसित किया जा रहा है, जिससे वहां के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के बेहतर अवसर मिल सकेंगे। उन्होंने प्राचीन गुरुकुल परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि शिक्षा का महत्व सदैव सर्वोच्च रहा है और राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश का कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के माध्यम से पढ़ाई के साथ संस्कार, कौशल और रोजगारोन्मुखी शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है। पिछले ढाई वर्षों में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक नवाचार किए गए हैं और आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) का होगा।

आने वाले समय में प्रदेश के 9 हजार स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रारंभ किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। स्कूलों में मध्यान्ह भोजन तो दिया जाता ही है, न्यौता भोजन का भी आयोजन किया जाता है। न्योता भोजन जन्मदिन, सालगिरह एवं निर्वाण दिवस की स्मृति में बच्चों को पौष्टिक भोजन कराया जाता है।

पीएम आवास के हितग्राहियों को बेटी की शादी पर मिलेगा निःशुल्क गैस कनेक्शन, विधायक रिकेश सेन की एक और बड़ी घोषणा

भिलाई नगर। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जनहित और सामाजिक कल्याण को केंद्र में रखकर लगातार नवाचारपूर्ण योजनाएं लागू कर रहे विधायक रिकेश सेन ने आज एक और महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास प्राप्त करने वाले परिवारों में बेटियों का विवाह होने पर नवविवाहित दंपत्ति को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत एक गैस सिलेंडर और एक गैस चूल्हा प्रदान किया जाएगा। इस नई पहल का शुभारंभ 10 अगस्त से किया जाएगा।

विधायक रिकेश सेन का कहना है कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों की बेटी के विवाह के बाद नए गृहस्थ जीवन की शुरुआत सुविधाजनक और सम्मानजनक हो, यही इस योजना का उद्देश्य है। उनका मानना है कि स्वच्छ ईंधन का उपयोग केवल सुविधा ही नहीं, बल्कि महिलाओं के स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण और बेहतर जीवन स्तर से भी जुड़ा हुआ है।

गौरतलब है कि वैशाली नगर विधानसभा में पिछले कुछ समय से विधायक रिकेश सेन लगातार ऐसी योजनाएं लागू कर रहे हैं, जिनका सीधा लाभ आम नागरिकों तक पहुंच रहा है। मात्र एक रुपये में चश्मा उपलब्ध कराने की योजना के माध्यम से हजारों लोगों की आंखों की जांच कर उन्हें चश्मे उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं मां-शिशु सुरक्षा कवच योजना के तहत नवजात शिशुओं और माताओं को

आवश्यक सामग्री से युक्त सुरक्षा किट प्रदान की जा रही है, जिससे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य को मजबूती मिल रही है।

इसके अलावा भाजपा कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों के सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा के लिए भी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत की गई है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और जरूरतमंद परिवारों की सहायता को लेकर विधानसभा क्षेत्र में लगातार नई पहलें की जा रही हैं, जिन्हें व्यापक जनसमर्थन भी मिल रहा है। आपको बता दें कि विधायक रिकेश सेन केवल विकास कार्यों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों की वास्तविक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर योजनाएं तैयार कर रहे हैं। यही कारण है कि उनकी पहलें सीधे आम लोगों के जीवन से जुड़ती दिखाई देती हैं।

स्थानीय नागरिकों ने भी इस नई घोषणा का स्वागत करते हुए कहा कि बिटिया के विवाह जैसे महत्वपूर्ण अवसर पर निःशुल्क गैस कनेक्शन उपलब्ध कराना आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित होगा। इससे नए परिवारों को सुरक्षित, स्वच्छ और सुविधाजनक रसोई की शुरुआत करने में मदद मिलेगी।

लगातार जनहित, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और गरीब कल्याण से जुड़ी योजनाओं के माध्यम से वैशाली नगर विधानसभा में विकास की नई कार्यशैली देखने को मिल रही है। विधायक रिकेश सेन का कहना है कि उनका उद्देश्य केवल योजनाओं की घोषणा करना नहीं, बल्कि उन्हें प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारकर प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक उनका लाभ पहुंचाना है। इसी सोच के साथ 10 अगस्त से शुरू होने वाली यह नई योजना भी वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र के हजारों परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सौगात साबित होने की उम्मीद है।

महापौर का निरीक्षण, निर्माण कार्य क्वालिटी के साथ और समय पर पूरा करने निर्देश

महापौर ने कंचन बाग में साफ सफाई एवं निर्माण कार्य का लिया जायजा

राजनांदगांव। कंचनबाग वार्ड नंबर 30 का जायजा लेने महापौर मधुसूदन यादव पहुंचे। यहां उन्होंने साफ सफाई एवं निर्माण कार्य की जानकारी ली और समय सीमा में कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उद्यान व सामुदायिक भवन मरम्मत करने स्टीमेंट तैयार करने तकनीकि अधिकारियों से कहा। वार्ड में साफ-सफाई का जायजा लेकर महापौर यादव ने स्वास्थ्य अमला से कहा कि बारिश में मौसमी बीमारी को देखते हुए साफ -सफाई का विशेष ध्यान रखा जाये। उन्होंने पानी भरान क्षेत्र के नालियों की समुचित सफाई हो, गड्ढें में भरे जल निकासी के लिए कच्ची नाली खोद निकासी कराए, समय समय पर दवाई का छिड़काव करें। उन्होंने कंचनबाग वासियों से रूबरू होकर कहा कि घर के आसपास साफ -सफाई रखे, घर में ही गिला सुखा कचरा अलग कर स्वच्छता दीदीयो को देवे, मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया से बचने एहतियात बरते। निर्माण कार्य निरीक्षण की कडी में कंचनबाग में निर्माणाधीन अन्नपूर्णा सामुदायिक भवन का जायजा लेकर कार्य में गति लाकर समय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

काम में क्वालिटी का ध्यान रखना जरूरी

महापौर ने निर्माण कार्य में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने तकनीकी अधिकारियों से कहा। निर्माण कार्य की सतत मानिटरिंग करे, जिससे समय सीमा में भवन पूर्ण हो और उसका लाभ क्षेत्रवासियों को मिल सके। कंचनबाग की महिलाओं द्वारा सामुदायिक भवन एवं उद्यान मरम्मत की मांग पर महापौर यादव ने अधिकारियों से दोनों का मरम्मत कराने स्टीमेंट तैयार करने कहा। उन्होंने कहा की प्रक्रिया कर जल्द इसका मरम्मत कराया जाएगा।

सिंगल यूज प्लास्टिक एवं सड़क बाधा पर 1100 रुपये का जुर्माना

भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई के आयुक्त एवं स्वास्थ्य अधिकारी के निर्देशानुसार जोन क्रमांक-01 के अंतर्गत वार्ड क्रमांक-07 राधिका नगर एवं वार्ड क्रमांक-08 कृष्णा नगर क्षेत्र में निगम की टीम द्वारा निरीक्षण एवं चालानी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पाए जाने, सड़क बाधा उत्पन्न करने तथा साफ-सफाई व्यवस्था संतोषजनक नहीं पाए जाने पर संबंधित दुकानदारों एवं प्रतिष्ठान संचालकों के खिलाफ जुर्माना वसूला गया। निगम की टीम ने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था का जायजा लेते हुए दुकानदारों को प्रतिष्ठानों के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने, सार्वजनिक स्थानों एवं सड़क पर किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करने तथा सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की समझाइश दी। निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि शहर में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। कार्रवाई के दौरान विनोद गुप्ता चाय सेंटर पर साफ-सफाई के लिए 100 रुपये, राम नारायण गंधर्व चाय सेंटर पर 50 रुपये, दीनू राम सेन सेलून दुकान पर 50 रुपये, जय जगन्नाथ डोसा सेंटर पर सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए 100 रुपये, शीर सागर डेली नीड्स पर 100 रुपये, हिना निर्मलकर सब्जी दुकान पर 100 रुपये तथा सुनीता किराना दुकान पर 200 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

कोहका स्थित 'वीरा जी के अंगना' में उमड़ा जनसैलाब, प्रदेशभर से पहुंचे शुभचिंतक

जनआशीर्वाद में बदला जन्मदिन समारोह : इंद्रजीत सिंह छोटू को हजारों प्रशंसकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर दी शुभकामनाएं

भिलाई। समाजसेवा, जनसहयोग और मानवीय मूल्यों के लिए अपनी अलग पहचान बना चुके युवा समाजसेवी इंद्रजीत सिंह छोटू का जन्मदिन इस वर्ष जनआशीर्वाद महोत्सव के रूप में मनाया गया। 20 जुलाई को कोहका स्थित 'वीरा जी के अँगना' में आयोजित भव्य जन्मदिन समारोह में हजारों की संख्या में पहुंचे प्रशंसकों, शुभचिंतकों एवं समर्थकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उन्हें जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं। सुबह से लेकर देर शाम तक शुभकामनाएं देने वालों का तांता लगा रहा। भिलाई, दुर्ग, रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों से लोग विशेष रूप से उन्हें बधाई देने पहुंचे। कार्यक्रम स्थल पर उमड़ी भारी भीड़ और जनसैलाब पूरे दिन चर्चा का विषय बना रहा। बड़ी संख्या में महिलाओं, युवाओं, वरिष्ठ नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, खेल प्रेमियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति ने समारोह को यादगार बना दिया।

हजारों लोगों की उपस्थिति बनी चर्चा का विषय-जन्मदिन समारोह में लोगों का उत्साह देखते ही बन रहा था। कार्यक्रम स्थल पर हजारों की तादाद में पहुंचे लोगों ने इंद्रजीत सिंह छोटू को पुष्पगुच्छ भेंट कर शुभकामनाएं दीं और उनके सामाजिक कार्यों की सराहना की। कई सामाजिक, धार्मिक, व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संगठनों ने भी सम्मानपूर्वक उनका अभिनंदन किया। स्थानीय लोगों के अनुसार कोहका क्षेत्र में किसी समाजसेवी के जन्मदिन पर इतनी बड़ी संख्या में लोगों का एकत्रित होना अपने आप में एक ऐतिहासिक अवसर रहा। पूरे दिन कार्यक्रम स्थल पर लोगों की आवाजाही जारी रही और यह आयोजन नगर में चर्चा का केंद्र बना रहा।

सेवा और जनसंपर्क ने दिलाया जनविश्वास-इंद्रजीत सिंह छोटू ने बिना किसी राजनीतिक पद के समाज के बीच अपनी अलग पहचान बनाई है। शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, सामाजिक सहयोग और जरूरतमंद परिवारों की सहायता जैसे क्षेत्रों में उनकी सक्रियता ने उन्हें जन-जन का प्रिय बना दिया है। वर्षों से निरंतर जनसेवा के कारण लोगों का उनके प्रति विश्वास और स्नेह लगातार बढ़ता गया है। जन्मदिन समारोह में उमड़ी भीड़ इसी जनविश्वास और सामाजिक स्वीकार्यता का प्रमाण मानी जा रही है।

प्रदेशभर से पहुंचे जनप्रतिनिधि एवं गणमान्य नागरिक-समारोह में विभिन्न क्षेत्रों के जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों, व्यापारिक संस्थाओं, खेल संगठनों एवं गणमान्य नागरिकों ने उपस्थित होकर इंद्रजीत सिंह छोटू को शुभकामनाएं दीं। कई अतिथियों ने उनके सामाजिक योगदान की सराहना करते हुए उन्हें समाज सेवा के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ने की शुभकामनाएं दीं।

स्वर्गीय बीरा सिंह के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे इंद्रजीत सिंह-समारोह के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इंद्रजीत सिंह छोटू अपने पूज्य पिता स्वर्गीय बीरा सिंह के सेवा, सहयोग और मानवता के आदर्शों को आगे बढ़ा रहे हैं। स्व. बीरा सिंह द्वारा समाज में स्थापित सेवा और सहयोग की परंपरा को इंद्रजीत सिंह नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं।

जन्मदिन पर इंद्रजीत सिंह छोटू का आभार संदेश-जन्मदिन पर मिले अपार स्नेह, सम्मान और शुभकामनाओं से अभिभूत इंद्रजीत सिंह छोटू ने सभी शुभचिंतकों के प्रति हृदय से आभार व्यक्त किया।

स्वत्वाधिकारी , प्रकाशक, एवं मुद्रक ज्वाला प्रसाद अग्रवाल द्वारा असमा पब्लिशर्स प्रा. लि. जयस्तंभ चौक, रायपुर, पिन - 492001 छत्तीसगढ़ से मुद्रित एवं झुलेलाल मंदिर के पीछे, पाटनकर कालोनी, सिंधी कालोनी, दुर्ग पिन- 491001 (छ.ग.) से प्रकाशित।
संपादक - ज्वाला प्रसाद अग्रवाल । e mail - jwalaexpress@gmail.com , मोबाईल- 9993590905, 7000489995